RNI No. 58061/93 | वर्ष - 21 | अंक - 228 | पृष्ठ - 8 | रु. 5/- | बेंगलूरु » बुधवार » 18-03-2026 | www.dakshinbharat.com | Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 पढ़ाई में तो अच्छे नंबर नहीं मिले, लेकिन क्रिकेट में 80 प्रतिशत अंक हासिल किए : सूर्यकुमार

6 परमाणु प्रसार पर अंकुश या उसे तेज करने की भूल?

7 अब समझ आई जिंदगी में संतुलन की अहमियत : हितेन तेजवानी

फर्स्ट टेक

एयर इंडिया के बोइंग 777-300 ईआर विमान ने छह साल बाद फिर भरी उड़ान

नई दिल्ली/भाषा। एयर इंडिया के पुराने बोइंग 777-300ईआर विमान ने छह साल से अधिक समय तक सेवा से बाहर रहने के बाद फिर से उड़ान भरना शुरू कर दिया है। एयरलाइन ने मंगलवार को बताया कि विमान वीटी-एएलएल को फिर से उड़ान के लायक बनाने के लिए 3,000 से अधिक नए प्रमुख पुर्जे लगाए गए और 4,000 से ज्यादा मरम्मत कार्य पूरे किए गए। ये सभी काम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के नागपुर स्थित मरम्मत एवं रखरखाव (एमआरओ) केंद्र में हुए। टाटा समूह के नियंत्रण वाली एयरलाइन ने कहा कि यह विमान फरवरी, 2020 में कई तकनीकी खामियों और पुराने हो चुके पुर्जों के कारण सेवा से हटा दिया गया था। लेकिन अप्रैल, 2025 में इसे फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया।

सरकार ने लोकसभा से जन विश्वास संशोधन विधेयक वापस लिया

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा से एक विधेयक वापस ले लिया जिसमें विश्वास आधारित शासन को सशक्त बनाने के लिए कई मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और तर्कसंगत बनाने के मकसद से कुछ अधिनियमों में संशोधन करने का प्रावधान है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन की अनुमति के बाद प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 वापस ले लिया। अधिकारियों ने बाद में कहा कि लोकसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद विधेयक को फिर से पेश किया जाएगा। किसी लंबित विधेयक को सदन की अनुमति के बाद वापस लिया जा सकता है, वहीं एक निरसन विधेयक लाकर किसी कानून को निरस्त किया जा सकता है।

लारीजानी को मार गिराया गया : नेतन्याहू

यरूशलम/भाषा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी को मार गिराने का दावा करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों का उद्देश्य ईरानी सरकार को कमजोर करना था ताकि ईरानियों को अपना भविष्य तय करने का मौका मिल सके। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, ''आज सुबह हमने अली लारीजानी को मार गिराया... उसके साथ ही हमने बासिज के कमांडर को भी मार गिराया - ये 'अपराधियों के सहायक' थे जो तेहरान और ईरान के अन्य शहरों की सड़कों पर लोगों को आतंकित कर रहे थे।''

18-03-2026 सूर्यास्त 6:30 बजे	19-03-2026 सूर्योदय 6:24 बजे
BSE 76,070.84 (+567.99)	NSE 23,581.15 (+172.35)
सोना 16,276 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 258,758 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

मेरा परिवार

हर भारतवासी है परिजन,
इसमें कोई भी नहीं वाद।
आखिर क्यों हम सब करते फिर,
कुछ परिवारों का ही निनाद।
भूलो सत्ता में पुरखों को,
छोड़ो सब ही परिवारवाद।
कुछ काम करो ऐसा जिससे,
रख सके आपको सभी याद।।

बच्चों को पौष्टिक भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना जरूरी है : राष्ट्रपति मुर्मू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं और यह आवश्यक है कि उन्हें पौष्टिक भोजन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो।

मुर्मू ने कहा कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य केवल सरकार की नहीं बल्कि सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ''जब शिक्षक, माता-पिता, सामाजिक संगठन, कॉर्पोरेट जगत और समाज के सभी वर्ग मिलकर काम करते हैं, तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और

स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिले। ये मूलभूत तत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास को संभव बनाते हैं।'' मुर्मू यहां राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 'अक्षय पात्र फाउंडेशन' द्वारा भोजन के पांच अरब पैकेट वितरण के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह अक्षय पात्र फाउंडेशन की एक सराहनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का विषय 'एक समृद्ध और शिक्षित भारत से एक विकसित भारत की ओर' है, जो वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के महत्व को रेखांकित करता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह आवश्यक है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो, जो राष्ट्र का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह साधन है जो किसी व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध अवसरों को निर्धारित करती है और उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ''यह परिवर्तन और सशक्तीकरण का एक प्रभावी माध्यम है। सशक्तीकरण और दक्षता निर्माण की प्रक्रिया बच्चों के स्कूल जाना शुरू करने के क्षण से ही आकार लेना शुरू कर देती है। स्कूल बच्चों को रोजमर्रा की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव प्रदान करता है।''

विपक्ष ने जनरल डिब्बों को लेकर झूठा विमर्श गढ़ा : वैष्णव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष पर रेलवे के जनरल और स्लीपर डिब्बों को लेकर फर्जी विमर्श गढ़ने और ''विकास विरोधी'' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके लिए गरीब सिर्फ वोट बैंक रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित होकर काम करती है।

वैष्णव ने वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सभी ट्रेनों में जनरल और स्लीपर डिब्बों की संख्या कुल डिब्बों का 70 प्रतिशत है। उन्होंने तीन चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के सत्तारूढ़ दलों को मंगलवार को ''विकास विरोधी'' करार देते हुए कहा कि इन्होंने इन प्रदेशों में रेलवे परियोजनाओं को अवरुद्ध कर रखा है। इन तीनों प्रदेशों तथा असम और पुडुचेरी में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है। मंत्री के जवाब के बाद, सदन ने रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों को कई विपक्षी सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। चर्चा में, 210 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। वैष्णव ने अपने जवाब में कहा, ''कई सांसदों ने फर्जी विमर्श गढ़ने की कोशिश की। आज भी जनरल और स्लीपर डिब्बों की संख्या कुल डिब्बों का 70 प्रतिशत है... हमारी प्रतिबद्धता गरीबों के प्रति है। यह हर कार्यक्रम में दिखाई देता है।'' वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''ये लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए और इनके लिए गरीब सिर्फ वोट बैंक रहा है।''

गिग श्रमिकों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गिग श्रमिकों को लेकर लोकसभा में पूछे गए लिखित प्रश्न और सरकार द्वारा दिए गए जवाब का हवाला देते हुए मंगलवार को दावा किया कि इन श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। राहुल गांधी ने बीते सोमवार को सरकार से लिखित प्रश्न किया था जिसकी प्रति उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर साझा की।

राहुल गांधी ने अपने 'व्हाट्सएप चैनल' पर पोस्ट किया, ''मैं हाल ही में गिग श्रमिकों के एक समूह से मिला

और उनकी समस्याओं को सुनकर लोकसभा में सरकार से सीधे सवाल पूछे कि क्या गिग श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी? कोई जवाब नहीं। बीमा योजनाओं में उनके दावे (फाइल, स्वीकृत, अस्वीकृत) का डेटा क्या है? कोई जवाब नहीं मिला।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''मैने यह भी पूछा गिग वर्कर (श्रमिक) की दुर्घटना और मौतों की संख्या बताई जाए? कोई जवाब नहीं मिला। सरकार के पास आईडी ब्लॉक, जाति-आधारित भेदभाव और महिला श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने की कोई योजना है? कोई जवाब नहीं मिला।''

राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार की ''चुप्पी'' दिखाती है कि गिग श्रमिकों का श्रम, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा इस सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। उन्होंने कहा, ''असलियत ये है कि नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जल्द ही देश में दो करोड़ से अधिक गिग कर्मचारी होंगे, लेकिन ई श्रम पोर्टल पर आज भी केवल करीब 8.8 लाख कामगार ही पंजीकृत हैं। बीमा योजनाओं में स्थिति और खराब है - जीवन ज्योति बीमा योजना में 23,831 और सुरक्षा बीमा योजना में 1.3 लाख गिग श्रमिकों का ही पंजीकरण है।''

सड़क निर्माण में कचरे का अधिक उपयोग हो : गडकरी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्राकृतिक संसाधनों की बचत के लिए सड़क निर्माण में नगर निकायों के कचरे के अधिक उपयोग पर मंगलवार को जोर दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एशियन एजुकेशन ग्रुप (एईजी) के 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह-2026 को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने कचरे के उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल सहित पुराने कचरे के चार पहाड़ हैं। सरकार ने 80 लाख टन कचरे को अलग-अलग करने और उसे सड़क निर्माण में उपयोग करने की पहल की है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे सहित विभिन्न परियोजनाओं में कचरे का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा, '' हमने सड़क निर्माण में नगर निकायों के कचरे का उपयोग करने का निर्णय लिया है ताकि हमें बजरी (एग्रीगेट) की व्यवस्था के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न करना पड़े। ''

उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में बम विस्फोट में 23 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल

मैदुगुरी (नाइजीरिया)/एपी। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर को निशाना बनाकर सोमवार रात किए गए संदिग्ध आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह संघर्ष ग्रस्त मैदुगुरी में हाल के वर्षों में सबसे भीषण हमलों में से एक है। इससे पूर्व स्थानीय निवासियों एवं आपात सेवाओं ने 'एसोसिएटेड प्रेस' (एपी) को बताया कि बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में 'मैदुगुरी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल' के प्रवेश द्वार पर और एक प्रमुख बाजार सहित भीड़ भाड़ वाले तीन स्थानों पर विस्फोट की सूचना मिली।

लेबनान ने दशकों के बाद इजराइल से सीधी वार्ता की पेशकश की

बेरूत/एपी। लेबनान सरकार ने दशकों की अपनी नीति को छोड़ते हुए इजराइल के साथ पहली बार सीधी वार्ता की पेशकश की है। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि वे पहले लड़ाई खत्म करना चाहते हैं और शायद अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी हो। यह पेशकश ऐसे समय की गई है, जब इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत सहित देश के अन्य हिस्सों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने इजराइल पर रॉकेट दागकर लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया और इसके जवाब में तेल अवीव द्वारा दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर की गई बमबारी में अबतक 850 लेबनानी मारे गए और दस लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने 1982 में लेबनान के गृहयुद्ध के दौरान हुए इजराइली आक्रमण के बाद पहली बार पिछले सप्ताह पड़ोसी देश से सीधी बातचीत की पेशकश की।

युद्ध क्षेत्र से दूसरा एलपीजी टैंकर भारत पहुंचा

अटके पड़े 22 अन्य जहाजों को लाने के प्रयास जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय ध्वज वाला दूसरा एलपीजी टैंकर युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकलने के बाद मंगलवार तड़के स्वदेश पहुंच गया। युद्ध क्षेत्र में फंसे अन्य 22 भारतीय जहाजों को सुरक्षित लाने के प्रयास जारी हैं।

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी टैंकर नंदा देवी, मंगलवार तड़के लगभग 2:30 बजे गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचा।

सोमवार को पहला जहाज, शिवालिक गुजरात के मुंदड़ा बंदरगाह पर पहुंचा था।

दोनों जहाज पर लगभग 92,712 टन एलपीजी हैं।

होर्मुज सुरक्षा मिशन में शामिल होने का मेरा प्रस्ताव : ट्रंप

वाशिंगटन/भाषा। ईरान के साथ युद्ध के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और अधिकतर

अन्य सहयोगी देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद करने के उनके आह्वान को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता ध्वस्त हो चुकी है और उन्हें अब नाटो देशों या किसी अन्य से सहायता की आवश्यकता नहीं है। पिछले सप्ताह ट्रंप ने यूरोपीय देशों और अन्य देशों से मदद का आह्वान किया था ताकि अहम समुद्री मार्ग 'होर्मुज जलडमरूमध्य' की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर अपने पोस्ट में कहा, हमारे अधिकतर नाटो सहयोगियों ने अमेरिका को सूचित किया है कि वे पश्चिम एशिया में ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ हमारे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते, जबकि लगभग हर देश इस बात से सहमत है।

'छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती के मॉडल पर काम कर रही है सरकार'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश में एकीकृत खेती के मॉडल पर काम कर रही है जिससे छोटी जोत वाले किसानों को भी फायदा होगा।

चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, ''सरकार ने छोटी जोत वाले किसानों के लिए एकीकृत खेती के अनेक मॉडल पर काम करना शुरू किया है और कई जगह उनका प्रदर्शन कर रहे हैं।''

उन्होंने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि छोटे किसान केवल एक फसल नहीं लगाएं, बल्कि खाद्यान्न, सब्जी, फल साथ में उगाने के अलावा वे मछली पालन, पशु पालन, वानिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में काम करें और छोटे किसान की खेती भी लाभ का धंधा बने।

चौहान ने तंबाकू के सेवन से हर साल देश में 13 लाख से अधिक लोगों की मौत होने का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि हम तंबाकू उत्पादक किसानों को अन्य वैकल्पिक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हमने केवल किसानों को यह नहीं कहा कि तंबाकू का उत्पादन छोड़ दो। हमने अनेक वैकल्पिक फसलें चिह्नित की हैं।'' उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादक किसानों को मक्का, मिर्च, शकरकंद, लोबिया, रागी, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और ज्वार जैसी विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बारिश

मंगलवार को बेंगलूरु में हल्की से मध्यम बारिश के बीच लोग सड़क पार करते हुए, जिससे शहर के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।

पाकिस्तान ने तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया

400 लोगों की मौत का अफगान सरकार का दावा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान ने रात भर ''सटीक हवाई हमले'' कर अफगानिस्तान भर में आतंकवादियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया, हालांकि अफगान सरकार ने इस्लामाबाद पर काबुल में एक पुनर्वास अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया, जिसमें कम से कम 400 लोग मारे गए।

पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया

कि सोमवार रात के उसके हवाई हमलों में काबुल में स्थित नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र को निशाना बनाया गया था।

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, ये नए हमले 26 फरवरी को शुरू किए गए ऑपरेशन 'गजब-लिल-हक' के जारी रहने के दौरान हुए हैं। पाकिस्तान ने 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा पर अफ़गान तालिबान बलों द्वारा कथित हमलों के जवाब में यह ऑपरेशन शुरू किया था।

सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन गजब-लिल-हक के तहत 16 मार्च की रात काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान शासन के आतंकवाद समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीक हवाई हमले किए।'' उन्होंने दावा किया कि काबुल में दो स्थानों पर स्थित तकनीकी सहायता ढांचे और गोला-बारूद भंडारण अड्डे पूरी तरह से नष्ट हो गए।

नीता अंबानी को केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरपर्सन नीता अंबानी को सोमवार को यहां कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज परिसर में प्रतिष्ठित केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया।

यह अवॉर्ड केआईआईटी, केआईएसएस और केआईएमएस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत की उपस्थिति में श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहन मुनासिंघे द्वारा प्रदान किया गया। समारोह में संस्थानों के वरिष्ठ पदाधिकारी, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य लोग शामिल हुए। अपने संबोधन में, नीता अंबानी ने कहा कि डॉ. सामंत ने शिक्षा के दो आधुनिक मंदिर केआईआईटी और केआईएसएस बनाए हैं। ये दोनों संस्थान हमारे देश के लिए गर्व का विषय हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित अवॉर्ड प्राप्त कर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका ही नहीं, बल्कि रिलायंस फाउंडेशन की पूरी टीम का है। नीता अंबानी ने कहा, 'आप लोगों ने यहां मुझे जो प्रेम और स्नेह दिया, उसे कभी नहीं भूलूंगी। केआईआईटी और केआईएसएस का दौरा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान जगन्नाथ की इस पावन भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूं। ओडिशा की संस्कृति, परंपराएं और मूल्य अत्यंत समृद्ध हैं। यहां के लोगों का प्रकृति के साथ गहरा और मज़बूत जुड़ाव है।' लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहा, 'यह तो बस शुरुआत है, आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। आपको बड़े सपने देखने चाहिएं और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करना चाहिए।'

आगामी रबी फसल में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार कदम उठाएगी : वित्त मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि आगामी रबी फसल के लिए किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है और उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण राज्यसभा में अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रही थीं।

उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लौटा दिया। इसके साथ ही संसद ने पूरक मांगों के दूसरे 'बैच' को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार वित्त वर्ष 2026 में अतिरिक्त 2.01 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकेगी। उन्होंने कहा कि अनुदान मांगों में उर्वरकों की सब्सिडी के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने उर्वरक और अन्य जरूरतों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और सरकार अशांत समय में भी एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है जिससे इससे मांग को पूरा करने में मदद मिल रही है। उन्होंने दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उसकी नीतियों के कारण दूरसंचार कंपनी की स्थिति खराब हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जब उसकी स्थिति सुधारने की कोशिश की है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है।

सरकार की प्राथमिकता 2033 तक सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की : निर्मला सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि स्वास्थ्य बीमा इस सरकार की प्राथमिकता है और उम्मीद है कि 2033 तक देश में सभी लोग बीमा के दायरे में आ जाएंगे।

वित्त मंत्री ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और 2024-25 के दौरान इसने देश में 58 करोड़ लोगों को कवर किया। उन्होंने कहा, ''स्वास्थ्य बीमा इस सरकार की प्राथमिकता है। वास्तव में, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2033 तक सभी को बीमा कवर मिल जाएगा।'' मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2025 में, सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य बाजार को मजबूत करना है। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने के लिए 2024 में नियम अधिसूचित किए। वित्त मंत्री ने कहा, ''अगर सामान्य तौर पर बीमा की बात करें, तो हमारे सामने एक चुनौती है।'' हालांकि बीमा कवरेज अब भी कम है लेकिन सरकार लक्षित सुधारों और किफायती उपायों के माध्यम से इस अंतर को पाटने के लिए प्रयासरत है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य बीमा बाजार का जिक्र करते हुए कहा, ''आज यह क्षेत्र काफी विकसित हो चुका है और 2024-25 में 1,17,505 करोड़ रु. तक पहुंच गया, जिसमें 58 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्राप्त है। इसमें सार्वजनिक, निजी और स्वतंत्र बीमा कंपनियों का संतुलित योगदान है।'' मंत्री ने कहा कि यदि बीमा कंपनियों द्वारा कोई भी कदाचार किया जाता है, तो नियामक उनके खिलाफ कार्रवाई करता है।

रेलवे की वित्तीय हालत सुधरी, रिकॉर्ड बजट आवंटन का सभी राज्यों को मिलेगा लाभ : वैष्णव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसले के कारण भारतीय रेल की वित्तीय हालत सुधरी है तथा परियोजनाओं में पारदर्शिता आई है।

वैष्णव ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि बजट में रेलवे को हुए रिकॉर्ड आवंटन का लाभ देश के प्रत्येक राज्य को मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 साल पहले रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिलाने का जो निर्णय लिया था, उसका फायदा रेलवे को अब भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। वैष्णव का कहना था, ''प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णय के कारण रेलवे को आगामी वित्त वर्ष के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला तथा हर साल अलग-अलग परियोजनाएं शुरू हो रही हैं और सभी परियोजनाओं में पारदर्शिता आई है।'' उन्होंने कहा कि रेलवे की वित्तीय हालत बहुत सुधरी है तथा इसके खाते अन्य विभागों की तरह ही पारदर्शी तरीके से सामने रखे जाते हैं। वैष्णव के अनुसार, रेलवे में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च कर्मचारियों और 32 हजार करोड़ रुपए का व्यय ऊर्जा पर खर्च हो रहा है।

एलपीजी की किल्लत से निपटने के लिए घरेलू, अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सभी प्रयास जारी : केंद्र सरकार

नागपुर/भाषा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच एलपीजी की किल्लत से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है।

उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए एलजीपी वितरकों की याचिका निपटारा कर दिया।

अदालत ने छह एलपीजी वितरकों की याचिका पर 12 मार्च को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया था। याचिका में ईरान युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट के बीच घरेलू रसोई गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी का भंडारण और आपूर्ति मौजूदा नीति के तहत होना चाहिए।

आतंक वित्त-पोषण मामला: न्यायालय ने शब्बीर शाह पर लगाईं कठोर शर्तें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने आतंकवाद के वित्त-पोषण मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत पर रिहाई का आदेश देते वक्त कुछ कठोर शर्तें भी लगाईं, जिनमें केवल एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, इसे हमेशा चालू रखना, निचली अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने से परहेज़ करना और इस मामले के बारे में मीडिया में कोई टिप्पणी न करना शामिल है।

न्यायालय ने शाह से यह भी कहा कि मामले की सुनवाई की अवधि के दौरान लगातार उपयोग कर सकने वाले अपने मोबाइल और/या लैंडलाइन नंबर की जानकारी विशेष सार्वजनिक अभियोजक (एसपीपी) के साथ साझा करें।

शीर्ष अदालत ने शाह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि यदि मुकदमा समय पर समाप्त होने की संभावना न हो तो निरंतर हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का कारण बन सकती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 12 मार्च के अपने आदेश में कहा कि मुकदमे के जल्दी निपटने की संभावना कम है और 74-वर्षीय शाह लंबी अवधि से हिरासत में रहे हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शाह को चार जून 2019 को गिरफ्तार किया था। पीठ ने कहा, ''शाह आठ साल से अधिक समय तक कारावास में रहे हैं। किसी आरोपी की लंबी हिरासत, विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जहां मुकदमे में बहुत कम या कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई हो, जमानत के मामले में निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक है।'' शीर्ष अदालत ने कहा, ''मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना और यह देखते हुए कि मुकदमे के जल्दी निपटने की संभावना कम है तथा अपीलकर्ता की लंबी हिरासत अवधि और उनकी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत देने के इच्छुक हैं।'' हालांकि पीठ ने शाह पर कड़ी जमानत शर्तें भी लागू की हैं, जो निचली अदालत द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों से भिन्न हैं।

पीठ ने कहा, ''वह निचली अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। यदि उनके (शाह के) पास पासपोर्ट है, तो वह उसे निचली अदालत के समक्ष जमा कर दें।

पीठ ने उन्हें निर्देश दिया कि वे हर पखवाड़े राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के जांच अधिकारी के पास बुधवार या बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच रिपोर्ट करें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि शाह न तो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।

मृतकों के बैंक खातों का विवरण वारिसों को क्यों न मुहैया कराया जाए: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से यह जानना चाहा कि मृत खाताधारकों के बैंक खातों की जानकारी उनके वैध उत्तराधिकारियों को उपलब्ध कराने में क्या बाधा है, और इस संबंध में स्पष्ट नीति तैयार करने की जरूरत बताई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

इस याचिका में मृत खाताधारकों के निष्क्रिय पड़े हुए जमा की जानकारी उनके उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्देश देने की अपील की गई है। पीठ ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने कई बैंक खातों का विवरण छोड़े बगैर मर जाता है, तो उसके वारिस उनमें जमा राशि के बारे में जानकारी कैसे जुटाएंगे? कानूनी वारिसों को जानकारी देने में क्या समस्या है? सरकार को इस पर नीति बनानी होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसे खातों का विवरण सार्वजनिक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने भी केंद्रीकृत और तलाश-योग्य डेटाबेस बनाने की सिफारिश की है, जिससे लोग अपने दिवंगत परिजनों के खातों का पता लगा सकें। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वी वेंकटरमण ने कहा कि यदि कोई वास्तविक वारिस सामने आता है तो उसे 'जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष' से राशि वापस कर दी जाती है। आरबीआई ने यह कोष 2014 में बनाया था जिसमें बैंकों की निष्क्रिय जमाओं को रखा जाता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और आरबीआई को इस मामले में नए हलफनामे दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की।

कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे की परीक्षा स्थगित

बेंगलूरु। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने रेलवे की परीक्षाएं केवल अंग्रेजी और हिंदी में कराने के खिलाफ कन्नड़ समर्थक संगठनों के प्रदर्शन के बाद मंगलवार को अचानक भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दीं। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के सदस्य बेंगलूरु और हुब्बल्ली में परीक्षा केंद्रों के बाहर एकत्र हुए और कन्नड़ में भी परीक्षा कराने की मांग की। दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) के एक अधिकारी ने कहा, विरोध प्रदर्शनों के कारण भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और अगली तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि दपरे ने मालगाड़ी प्रबंधक के 194 पद समेत 295 पदों को भरने के लिए मंगलवार को परीक्षा निर्धारित की थी। इस घटनाक्रम के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कन्नड़ भाषी उम्मीदवारों के साथ इस तरह का अन्याय न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया और मांग की कि रद्द की गईं परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित की जाएं और कन्नड़ भाषा में भी परीक्षा देने की व्यवस्था की जाए।

कर्नाटक रक्षा वेदिके भर्ती परीक्षाओं से स्थानीय भाषा को हटाने के कदम का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि इससे स्थानीय उम्मीदवारों को परीक्षा देने से रोका जा सकता है। परीक्षा स्थगित होने का स्वागत करते हुए संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी किए बिना परीक्षाएं दोबारा आयोजित की गईं तो वे विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे।

भोजशाला विवाद : संघ नेता ने कहा, ''सभी तथ्य सामने आ गए हैं, अदालत का हर निर्णय स्वीकार करेंगे''

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर/भाषा। धार के भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर जारी कानूनी विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को कहा कि इस मामले से जुड़े सभी तथ्य मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सामने आ चुके हैं और वह अदालत का हर निर्णय स्वीकार करेंगे।

संघ के मालवा प्रांत (इंदौर-उज्जैन संभाग) के प्रमुख प्रकाश शास्त्री ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ''हमने इस मामले (भोजशाला विवाद) में अलग से कोई दृष्टिकोण नहीं रखा है और सभी तथ्य अदालत के सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भोजशाला विवाद का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। शास्त्री ने कहा, इस मामले में अदालत का जो भी निर्णय आएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे।'' उन्होंने यह बात उस सवाल पर कही जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा गया था कि क्या भोजशाला का ऐतिहासिक विवाद अपने समाधान की ओर बढ़ रहा है? एएसआई की 2,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भोजशाला परिसर में धार के परमार राजाओं के शासनकाल की एक विशाल संरचना मस्जिद के मुकाबले पहले से विद्यमान थी और वहां वर्तमान में मौजूद एक विवादित ढांचा प्राचीन मंदिरों के हिस्सों का फिर से इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था।

भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष संभवतः 11वीं सदी के इस स्मारक को मस्जिद बताता रहा है। महेश्वर से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री मोनालिसा भोंसले की शादी को कथित 'लव जिहाद' से जोड़े जाने को लेकर खड़े हुए विवाद पर संघ नेता शास्त्री ने इस अंतरधार्मिक विवाह का सीधा जिक्र किए बगैर कहा कि 'लव जिहाद' की घटनाएं 'संस्कारों के अभाव' के कारण सामने आती हैं और यह पूरे देश के लिए चिंतनीय विषय है। शास्त्री ने कहा कि अगर परिवारों में लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक करके उचित संस्कार दिए जाएं, तो ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी।

मोनालिसा ने पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि हासिल करने के बाद अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। मोनालिसा की फरमान खान नामक व्यक्ति के साथ केरल में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई शादी को युवा अभिनेत्री के पिता और उनके करीबी लोगों ने कथित 'लव जिहाद' का मामला बताया है।

तूफान, ओलावृष्टि के कारण नैनीताल में 24-36 घंटे तक बिजली गुल रही, 80 हजार लोग हुए प्रभावित

नैनीताल/भाषा। नैनीताल में रविवार को तूफान और भीषण ओलावृष्टि के दौरान जमीन से उखड़े पेड़ों और उनकी टूटी टहनियों की चपेट में आकर बिजली की कई तारें नीचे आ गईं जिससे शहर के एक बड़े हिस्से में 24 से 36 घंटे तक बिजली गुल रही। बिजली गुल होने से पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जिससे निवासियों, पर्यटन पर निर्भर व्यवसायों और यहां तक कि अदालती कार्यवाही भी प्रभावित हुई ।

पद्मपुरी, ओखलकांडा, सूखाताल और पाइंस सहित नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों की करीब 80,000 की जनसंख्या इससे सर्वाधिक प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन (यूपीसीएल) को इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही से अनुमानित 5060 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि यूपीसीएल की टीम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए बिजली बहाल करने के लिए लगातार काम में जुटी हैं। हालांकि, यूपीसीएल के कुमाऊं जोन के मुख्य अभियंता राजेंद्र गुंजयाल ने कहा कि ''बिजली बहाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है जबकि तूफान से हुए अन्य नुकसानों का विस्तृत आकलन बाद में किया जाएगा।'' बिजली गुल होने से स्थानीय व्यवसायियों विशेषकर पर्यटन पर निर्भर व्यवसायियों की मुश्किलें और बढ़ गईं, जो पहले से ही एलपीजी की कमी से जूझ रहे थे।

जनगणना-2027 दिव्यांगता डेटा रिकॉर्ड करने का ऐतिहासिक अवसर : आठवले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को कहा कि जनगणना-2027 दिव्यांगता की सभी 21 मान्यता प्राप्त श्रेणियों का सटीक डेटा एकत्रित करने और दिव्यांगों से जुड़े नीति निर्माण को सक्षम बनाने का 'ऐतिहासिक अवसर' प्रदान करेगी।

आठवले ने ''दृश्यमान से परे : दिव्यांगता समावेशन पर सांसदों के लिए मार्गदर्शिका'' के लोकार्पण अवसर पर कहा कि 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के लागू होने के बाद पहली बार इस तरह का डेटा एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर गणना और भिन्न-भिन्न प्रकार के डेटा सरकार को प्रभावी कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा और दिव्यांग व्यक्तियों के बेहतर समावेशन को सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री आठवले ने कहा, ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एक महत्वपूर्ण सुधार कानून था, जिसने दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता दी, जो कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का प्रमाण है तथा इसके जरिये भारत को भी संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग अधिकार सम्मेलन के अनुरूप बनाया जा सका।'' नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल्स (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि यह मार्गदर्शिका सांसदों को कानूनी प्रावधानों को व्यावहारिक नीतियों में बदलने और दिव्यांग व्यक्तियों की भविष्य की बाधाओं को दूर करने में मदद के उद्देश्य से तैयार की गई है।

देश में 40 प्रतिशत स्नातकों को नहीं मिल पा रही नौकरी : रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। देश में 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 6.3 करोड़ स्नातकों में से 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं और स्नातक होने के एक वर्ष के भीतर बहुत कम लोगों को ही निश्चित वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट 'भारत में कामकाज की स्थिति-2026' में पाया गया कि बेरोजगार के रूप में पंजीकरण कराने के एक वर्ष के भीतर केवल करीब सात प्रतिशत स्नातकों को स्थायी वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्नातक बेरोजगारी दर उच्च बनी हुई है। 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर करीब 40 प्रतिशत और 25 से 29 वर्ष आयु वर्ग में 20 प्रतिशत है।

इसमें कहा गया, '' स्नातक होने के एक वर्ष के भीतर केवल एक छोटा हिस्सा ही स्थायी वेतन वाली नौकरी हासिल कर पाता है। हाल के वर्षों में स्नातकों की बढ़ती संख्या के कारण यह समस्या और बढ़ गई है।'' रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में युवा आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा में नामांकन दर भी बढ़ी है जिससे युवा स्नातकों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें कहा गया, ''इस स्थिति से उच्च बेरोजगारी दर के साथ बेरोजगार स्नातकों की संख्या भी बढ़ गई है। 2023 तक 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 6.3 करोड़ स्नातकों में से 1.1 करोड़ बेरोजगार थे।'' रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा से जुड़े कई अंतर को पाटने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें कहा गया, '' उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात भारत के विकास स्तर के अनुरूप है। शिक्षा तक पहुंच में लड़का-लड़की और जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक बाधाएं कम हुई हैं (हालांकि अब भी काफी काम बाकी है)...। हालांकि, इसके साथ रोजगार में प्रभावी बदलाव नहीं हुआ है। युवा स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर लगातार ऊंची बनी हुई है। शिक्षा तक पहुंच असमान है। हालांकि स्कूल से कार्यस्थल तक का सफर अनिश्चित है और कई लोगों के लिए यह स्थायी, लाभकारी रोजगार में तब्दील नहीं हो पाता।''

रासुका के तहत मेरी हिरासत को रद्द किया जाना सभी के लिए लाभदायक : वांगचुक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जेल से रिहा होने के बाद पहली सार्वजनिक टिप्पणी में मंगलवार को कहा कि रासुका के तहत उनकी हिरासत को रद्द करना ''सभी के लिए फायदेमंद'' है और केंद्र ने लद्दाख के लोगों के साथ सार्थक संवाद के लिए विश्वास कायम करने की दिशा में पहल की है।

वांगचुक ने पत्नी और एचआईएएल की सह-संस्थापक गीतांजलि जे अंगमो के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य रचनात्मक संवाद प्रक्रिया शुरू करना है।

उन्होंने कहा, ''हमें अदालत में जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं थी। मैं सभी पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति चाहता हूं।''

वांगचुक ने सरकार की पहल को ''विश्वास कायम करने और सार्थक, रचनात्मक संवाद को सुविधाजनक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम'' करार दिया।

जलवायु कार्यकर्ता ने कहा, ''उन्होंने रचनात्मक और सार्थक संवाद का प्रस्ताव रखा है। यही हम चाहते थे, और इसके लिए हमें

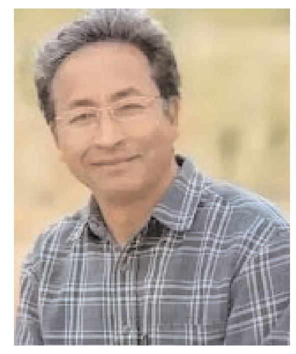

बहुत संघर्ष करना पड़ा, दिल्ली तक पैदल चलना पड़ा, अनशन पर बैठना पड़ा। लद्दाख में सभी आंदोलन संवाद प्रक्रिया शुरू करने के लिए हैं।'' उन्होंने कहा, ''आमतौर पर लोग हथियार उठाते हैं और सरकार बातचीत की अपील करती है। यहां लोग सरकार से बातचीत शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं।''

वांगचुक से अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह लद्दाख की यात्रा करेंगे और लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केएडी) के नेताओं से परामर्श करेंगे, जो पिछले पांच वर्षों से राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची का विस्तार देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

नए सिरे से आंदोलन शुरू करने के सवाल पर जलवायु कार्यकर्ता ने कहा, ''मैंने हमेशा कहा है कि मैं भूख हड़ताल पर नहीं बैठना चाहता। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अब जबकि सरकार ने पहल की है, हमें उम्मीद है कि इससे एक अच्छा उदाहरण पेश होगा।''

वांगचुक (59) को पिछले साल 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें लद्दाख में आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद हिरासत में लिया गया था। उक्त हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी।

केंद्र सरकार द्वारा वांगचुक की नजरबंदी को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के बाद उन्हें शनिवार को जोधपुर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।

उगादि रौनक

बेंगलूरु के केआर मार्केट में 'उगादि' त्योहार की जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। लोग घर के दरवाजों को सजाने के लिए ताजे आम के पत्ते और 'बेवु-बेला' (नीम-गुड़) के लिए नीम के फूल खरीदते नजर आए। यह त्योहार वसंत के आगमन और नई शुरुआत का प्रतीक है, जो इस वर्ष 19 मार्च को मनाया जाएगा।

बेलगावी में जल्द स्थापित होगा आईटी और सेमीकंडक्टर पार्क : प्रियंक खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बेलगावी को एक विकासोन्मुखी और न्यायसंगत राज्य बनाना है जो आईटी पार्क/सेमीकंडक्टर पार्क बनाकर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेगा।

मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, जब विधानसभा सदस्य अभय पाटिल ने बेलगाम को विकासोन्मुखी राज्य बनाने और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए वहां आईटी पार्क और सेमीकंडक्टर पार्क बनाने का अनुरोध किया, तो मंत्री ने उत्तर दिया कि सरकार ने बेलगावी को विकासोन्मुखी राज्य बनाने और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए वहां आईटी पार्क/सेमीकंडक्टर पार्क बनाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।

मंत्री ने कहा कि आईटी प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, एक्सेलेरेटर नेटवर्क और सीड फंड सहायता, तकनीकी त्वरण, समग्र विकास और भविष्य की प्रौद्योगिकी, निपुण कर्नाटक, आइडिया2पीओसी एलिवेट (अनुदान सहायता), राजीव गांधी उद्यमिता कार्यक्रम, एलिवेट महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर नवाचार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बेलगावी में आईटी पार्क/सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए प्रस्तावित भूमि को राज्य सरकार को सौंपने हेतु 8 जनवरी 2021 को भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया था। चूंकि रक्षा विभाग ने अभी तक भूमि राज्य सरकार को वापस करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए आईटीबीटी मंत्री ने 9 सितंबर 2021 को पुनः पत्र लिखा। 21 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा और उसी तिथि को मुख्य सचिव ने रक्षा सचिव को पत्र लिखकर कर्नाटक सरकार को भूमि सौंपने का अनुरोध किया। मंत्री ने कहा कि बेलगावी के तिलकवाड़ी स्थित कलामंदिर भवन में कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (केडीईएम) के सहयोग से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर (जीटीडी) स्थापित करने के लिए भवन को विभाग को सौंपने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए कार्रवाई : सुधाकर

बेंगलूरु। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर ने कहा कि राज्य के निजी सहायता प्राप्त प्रथम श्रेणी के कॉलेजों में ग्रुप 'सी' और 'डी' कैडर के रिक्त गैर-शिक्षण पदों को आउटसोर्सिंग के आधार पर भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

मंगलवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान परिषद सदस्य श्रीमती बल्किस बाबू के ध्यान में लाए गए एक व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (कॉलेज शिक्षा) नियम, 2003 के अनुसार, 1 मार्च 2001 को या उसके बाद रिक्त होने वाले सभी गैर-शिक्षण पदों को 'स्थायी रूप से 'गैर-सहायता प्राप्त' पद माना जाता है। इन पदों पर सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अपने संसाधनों से भरा जाएगा और वेतन का वहन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जाएगा। नवीनतम सरकारी परिपत्र (दिनांक: 07.06.2024) के अनुसार, राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत ग्रुप 'डी' और ग्रुप 'सी' के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

कर्नाटक सरकार ने गन्ना किसानों को 100 रुपये प्रति टन की सहायता देने का वादा पूरा किया : मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के गन्ना मंत्री शिवानंद पाटिल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अपना वादा पूरा किया है। पाटिल ने दावा किया कि इस वर्ष अधिकतर किसान सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं।

विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एमएलसी एन रविकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए पाटिल ने कहा कि सरकार ने किसानों से संबंधित कई मांगों पर पहले ही कार्रवाई कर ली है और किसानों तथा चीनी मिल दोनों के लिए सहायता जारी रखे हुए है। मंत्री ने कहा, ''कर्नाटक के इतिहास में, अगर किसी सरकार ने गन्ना किसानों को दो बार मदद दी है, तो वह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सरकार है। इस बार भी, हमने सरकार की ओर से 50 रुपये प्रति टन और फैक्टरी मालिकों की ओर से 50 रुपये प्रति टन देने का वादा किया था, और हमने वह वादा पूरा किया है।'' उन्होंने कहा कि किसान संकट में नहीं हैं; वास्तव में, अधिकांश किसान इस वर्ष संतुष्ट हैं, और सरकार उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

निविदा सूचना सं: ECN-TRD-03-2026
दिनांक: 12.03.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं:

कार्य का नाम	अनुमानित लागत
गिनिगेरा और रायचूर विभाग में 2x25 केवी ओएचई, पीएसआई सिस्टम (टीएसएस का, एसपी का और एसएसपी का), जीएसएस से टीएसएस तक ट्रैन्समिशन लाईन की प्रावधान, इलेक्ट्रिकल साम्य कार्य, इंजीनियरिंग कार्य और सिग्नलिंग व दूरसंचार कार्य के डिजाईन, आपूर्ती, स्थापना, कमीशनिंग (166 आरकेएम / 204 टीकेएम)	रु. 3,11,60,07,445.45/-

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथिः 10.07.2026, 11:00 बजे तक

विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में

उप मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर/कर्षण वितरण-2/निर्माण/बेंगलूरु

PUB/1001/AAMO/PRB/SWR/2025-26

रेलओन ऐप डाउनलोड करें। रेलओन इंडियन रेलवे का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप है। पैसेंजर अपनी उंगलियों पर आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफ़ॉर्म टिकट और सीज़न पास बुक कर सकते हैं, पीएनएर स्थिती परिशीलन कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और कई दूसरी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। रेलओन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें और 3% तक छूट का फ़ायदा उठाएँ।

South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिसों का जवाब देने के लिए अधिकारियों को निर्देश : अध्यक्ष यूटी खादर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। लेकिन विभाग निर्धारित समय के भीतर उत्तर नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष यूटी खादर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आने वाले दिनों में निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्रदान करें। इस संबंध में, मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, विभिन्न विभाग निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सदन को स्पष्ट किया कि किस विभाग द्वारा कितने जवाब प्रस्तुत किए गए हैं।

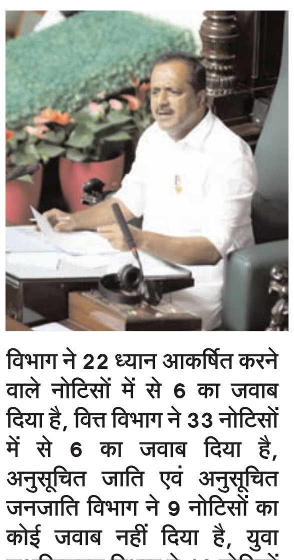

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 22 ध्यान आकर्षित करने वाले नोटिसों में से 6 का जवाब दिया है, वित्त विभाग ने 33 नोटिसों में से 6 का जवाब दिया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग ने 9 नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया है, युवा सशक्तिकरण विभाग ने 10 नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया है, सहकारिता विभाग ने 12 नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक नोटिस का जवाब दिया है। जल संसाधन विभाग ने 33 नोटिसों में से 4 का जवाब दिया है, शहरी विकास विभाग ने 23 नोटिसों में से 8 का जवाब दिया है, गृह विभाग ने 35 नोटिसों में से 26 का जवाब दिया है, विधि विभाग ने 5 नोटिसों में से 3 का जवाब दिया है, पर्यटन विभाग ने 25 नोटिसों में से एक का जवाब दिया है और लघु सिंचाई विभाग ने 19 नोटिसों में से 13 का जवाब दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 2 ध्यान आकर्षित करने वाले नोटिसों में से 2 का जवाब दिया है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने पर ध्यान देने का निर्देश दिया।

'मोबाइल अस्पतालों' में होगी बेहतर व्यवस्थाएं : मंत्री दिनेश गुंडूराव

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के ग्रामीण, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मंगलवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान, मंत्री ने नियम 72 के तहत परिषद सदस्य एफ. एच. जक्कप्पनवर द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की।

वर्तमान में, राज्य भर में कुल 81 मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ कार्यरत हैं। इन्हें आवश्यकतानुसार जिलावार वितरित किया गया है। पीएम-जनमान योजना के तहत, 5 जिलों और उन गांवों में मधुमक्खी पालक और कोरगा समुदायों के विकास को प्राथमिकता दी गई है जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है। स्वास्थ्य केंद्रों से दूर स्थित और परिवहन सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। मोबाइल इकाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार के 'घाटी शक्ति' पोर्टल के माध्यम से इनकी आवाजाही पर लगातार नज़र रखी जा रही है। मौजूदा इकाइयों की सेवा 19 दिसंबर से नए प्रारूप में शुरू कर दी गई है और मंत्री जी ने पिछले अनुदानों के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज कर दिया है।

मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और प्रयोगशाला तकनीशियनों की कमी को दूर करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सुसज्जित वाहन और आवश्यक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक मोबाइल यूनिट के लिए एक दिन में एक गांव का सुबह और दूसरे गांव का दोपहर में दौरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन दौरों के दौरान संबंधित क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मरीजों के घर तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए मीलों पैदल चलने की जरूरत न पड़े।

देवेगौड़ा को सोनिया का जवाब :

आपकी चिंताओं का संज्ञान लिया

नई दिल्ली/बेंगलूरु। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जवाबी पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने संसद के अंदर व्यवधान और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी उनकी चिंताओं का संज्ञान लिया है। सोनिया गांधी ने उगादी पर्व की पूर्व संध्या पर देवेगौड़ा को शुभकामनाएं भी दीं।

सोनिया गांधी को संबोधित पत्र में देवेगौड़ा ने सोमवार को कहा था कि संसद और उसके परिसर में बिना सोचे-समझे, जो अराजकता फैलाई गई है, उससे वह बहुत परेशान हैं। यह अराजकता मुख्य रूप से विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई है।''

जनता दल (एस) के नेता ने कहा, ''मुझे दृढ़ता से लगता है कि विपक्ष के नेता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद के अंदर और उसके परिसर में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न किया है।'' पत्र का जवाब देते हुए, ''सोनिया गांधी ने कहा, प्रिय देवेगौड़ा जी, मुझे अभी आपका 16 मार्च 2026 का पत्र मिला है। मैंने इसे ध्यान से पढ़ा है और आपकी चिंताओं को संज्ञान में लिया है।'' उन्होंने देवेगौड़ा के दो पन्ने के पत्र के संक्षिप्त उत्तर में कहा, मैं उगादी की पूर्व संध्या पर आपको शुभकामनाएं देती हूं।''

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-(आईआरईपीएस) निविदा सूचना सं: 51 UBL 2025-26 दिनांक: 11.03.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं:

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	हुबली विभाग: वरिष्ठ विभागीय इंजीनियर / प्रधान कार्यालय / हुबली क्षेत्राधिकार पर वेल्डिंग का आपूर्ती।	रु. 1,15,73,588.00
2	हुबली विभाग: हुबली यार्ड में पिट लाईन का सदृढ़ीकरण।	रु. 2,31,94,626.00
3	हुबली विभाग: हुबली रेलवे स्टेशन पर तूफानी जल निकास के साथ साथ प्रस्तावित स्टेशन एप्रोच रोड़ का निर्माण और लोवर सर्क्युलेटिंग प्रदेश पर लैंड स्केपिंग पर सुधारण कार्य।	रु. 5,36,06,217.00
4	हुबली विभाग: हुबली विद्यारण्य नगर रेलवे कॉलोनी पर क्वार्टर नं. 1327 (ए-पी) के बदले टाईप-2 (16 यूनिट) प्रस्तावित निर्माण।	रु. 4,06,71,104.00
5	हुबली विभाग: वरिष्ठ विभागीय इंजीनियर / पश्चिम / हुबली क्षेत्राधिकार पर वेल्डिंग का आपूर्ती।	रु. 1,11,01 ,321.00
6	हुबली विभाग: कुडगी (केडीजीआई) - कुडगी पर प्रस्तावित नई रनिंग रूम का निर्माण (24 कमरें / 48 बेड)	रु. 3,22,39,095.00

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथिः 09.04.2026, 11:00 बजे तक

विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में

वरिष्ठ विभागीय इंजीनियर/समन्वय हुबली

PUB/1000/AAMO/PRB/SWR/2025-26

रेलओन ऐप डाउनलोड करें। रेलओन इंडियन रेलवे का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप है। पैसेंजर अपनी उंगलियों पर आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफ़ॉर्म टिकट और सीज़न पास बुक कर सकते हैं, पीएनएर स्थिती परिशीलन कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और कई दूसरी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। रेलओन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें और 3% तक छूट का फ़ायदा उठाएँ।

South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड की एसएसएलसी परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस साल रिकॉर्ड 9,02,889 छात्र परीक्षा में बैठेंगे। बेंगलूरु के शेषाद्रिपुरम कॉलेज सहित राज्य भर के 2,871 केंद्रों पर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने एसएसएलसी परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। राज्य में एसएसएलसी परीक्षा 18 मार्च से शुरू होगी और मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को सदन में परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दीं। वर्तमान में 8,65,968 बच्चे एसएसएलसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं और परीक्षाएं तीन चरणों में आयोजित की जाती हैं। पहले चरण में असफल होने पर भी छात्र को दूसरे और तीसरे चरण में परीक्षा देने का अवसर मिलता है। उन्होंने एसएसएलसी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को साहस के साथ परीक्षा देने और चिंतित न होने की सलाह दी।

शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने एसएसएलसी परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पहले बच्चे परीक्षा के दबाव में परीक्षा देते थे।

अब शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे बिना किसी चिंता के परीक्षा दें क्योंकि परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जा रही है और छात्रों को शुभकामनाएं दीं।

वहीं विपक्ष के नेता आर. अशोक ने एसएसएलसी परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित न करें। हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में चेतावनी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने विधायकों के सवालों के जवाब में देरी पर मंत्रियों को फटकार लगाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने विधायकों के सवालों के जवाब देने में हुई देरी को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों को फटकार लगायी है और चेतावनी दी कि इस चूक से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है।

सोमवार को सभी मंत्रियों को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि कर्नाटक विधानसभा के 16वें सत्र के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए कई सवालों का जवाब नहीं दिया गया है और विभागों तथा अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

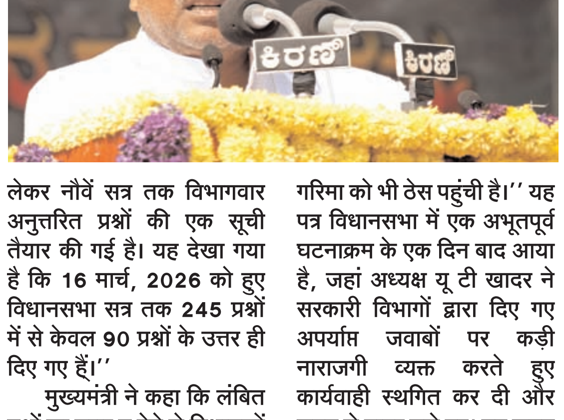

सिद्दरामय्या ने कहा, ''16वीं कर्नाटक विधानसभा (2023-26) के पहले सत्र से लेकर नौवें सत्र तक विभागवार अनुत्तरित प्रश्नों की एक सूची तैयार की गई है। यह देखा गया है कि 16 मार्च, 2026 को हुए विधानसभा सत्र तक 245 प्रश्नों में से केवल 90 प्रश्नों के उत्तर ही दिए गए हैं।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित प्रश्नों का उत्तर न देने से विधायकों को सदन की कार्यवाही में प्रभावी ढंग से भाग लेने में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा, ''इससे न केवल सरकार को बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ी है बल्कि विधायकों के अधिकारों और सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंची है।'' यह पत्र विधानसभा में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के एक दिन बाद आया है, जहां अध्यक्ष यू टी खादर ने सरकारी विभागों द्वारा दिए गए अपर्याप्त जवाबों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी और सदन से बाहर चले गए। यह कदम विपक्ष के नेताओं के विरोध के बाद उठाया गया, जिन्होंने सरकार पर अध्यक्ष की बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. 08/MYS/2026, दिनांक: 13.03.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार ई-नीलामी / ई-निविदा हेतु निविदादाताओं को आमंत्रित करते हैं:

क्र.सं.	विवरण संक्षेप में	अनुमानित लागत
1	**उप कार्य-1: मैसूरु:** वीआरसी कॉलोनी के लिए एसएसई/इलेक्ट्रिकल/जनरल रखरखाव कार्यालय का निर्माण। **उप कार्य-2: मैसूरु:** मैसूरु पर क्रू लॉबी का सदृढ़ीकरण और उन्नयन। **उप कार्य-3:** हॉल्ट स्टेशनों पर कम लागत वाली पीएफ शेल्टरों का प्रावधान (एमआरएलए, बीओजीपी, केआरएनयू, एसजेपीएम, टीएस्कएम, केएलवायएच, एआरएनएच)।	रु. 2,36,06,712/-
2	**सहायक विभागीय इंजीनियर/अरसीकेरे उप-विभाग:** संपिगे रोड - अरसीकेरे (एसपीजीआर-एएसके) विभाग, अरसीकेरे - बीरूर जं. (एएसके-आरआरबी) विभाग और होले नरसीपूर - अरसीकेरे (एचएलएल-एएसके) विभागों में आरयूबीयों पर स्टैंडर्ड हेट गॉज का प्रावधान।	रु. 2,31,23,558/-
3	**बीरूर जं. - तालगुप्पा (आरआरबी-टीएलजीपी) विभाग:** शिवपुर - तरीकेरे (एसपीवी-टीकेई) स्टेशनों के बीच कि.मी. 16/700-800 पर एप्रोच रोड़, रीटेनिंग वॉल का प्रस्तावित सुरक्षा सुविधाओं का सुधारण और आरओबी नं. 238 पर रेल बैरिकेडिंग का प्रावधान।	रु. 1,38,75,263/-
4	**उप कार्य-1: अमरावती कॉलोनी (एवीसी-केटीवाय) विभाग:** बेन्नेहल्ली - कोट्टूरु (बीईएचआई-केटीवाय) स्टेशनों के बीच किमी. 79/200-300 पर सब-वे का निर्माण करने से एलसी. नं. 60 को हटाना। **उप कार्य-2:** बेन्नेहल्ली - कोट्टूरु (बीईएचआई-केटीवाय) स्टेशनों के बीच किमी. 79/200-300 पर सब-वे का निर्माण करने से एलसी. नं. 60 को हटाने का संबंध में आरसीसी बॉक्स सेग्मेंट का लॉंचिंग कार्य।	रु. 8,68,63,945/-

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथिः 06.04.2026, 11:00 बजे तक

विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में

वरिष्ठ विभागीय इंजीनियर / समन्वय / मैसूरु

PUB/1005/AAMO/PRB/SWR/2025-26

रेलओन ऐप डाउनलोड करें। रेलओन इंडियन रेलवे का ऑल-इन-वन रेलवे ऐप है। पैसेंजर अपनी उंगलियों पर आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट, प्लेटफ़ॉर्म टिकट और सीज़न पास बुक कर सकते हैं, पीएनएर स्थिती परिशीलन कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और कई दूसरी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। रेलओन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें और 3% तक छूट का फ़ायदा उठाएँ।

South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

पहली बार तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगाएगा वन विभाग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर के झालाना जंगल से शहर में आने वाले तेंदुओं की बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर राजस्थान वन विभाग ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनमें रेडियो कॉलर लगाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मुख्य वन्यजीव संरक्षक के सी अरुण प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगाने से न केवल वास्तविक समय पर उनके स्थान का पता चल सकेगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में बचाव और नियंत्रण की कार्रवाई भी संभव हो पाएगी।

उन्होंने कहा, झालाना लेपर्ड रिजर्व वर्तमान में 30 से अधिक तेंदुए हैं। यह जंगल चारों तरफ से रिहायशी इलाकों से घिरा हुआ है। इस कारण आए दिन तेंदुओं की हलचल आबादी वाले इलाकों में देखी जाती है। पिछले एक साल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बना रहता है। मुख्य वन्यजीव संरक्षक ने कहा कि इन्हीं चुनौतियों से निपटने और वन्यजीवों तथा इंसानों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेडियो कॉलर तकनीक का सहारा लेने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु की एक कंपनी से रेडियो कॉलर मंगवा लिए गए हैं। आगामी एक सप्ताह में तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगा दिए जाएंगे। तेंदुओं के लिए रेडियो कॉलर बाघों की तुलना में हल्के होंगे। के.सी. प्रसाद ने बताया कि रेडियो कॉलर की मुख्य विशेषता जीपीएस ट्रैकर है, जो तेंदुओं की गतिविधियों और उनके प्राकृतिक आवास पर डेटा इकट्ठा करता है।

उन्होंने कहा, डेटा का विश्लेषण वन अधिकारियों को तेंदुए की गतिविधियों का अनुमान लगाने में मदद करेगा। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में रेडियो कॉलर प्रयोग के आधार पर लगाया जाएगा। रेडियो कॉलर उन तेंदुओं पर लगाया जाएगा जिनकी गतिविधि शहरी क्षेत्र में ज्यादा रहती है। अधिकारियों ने बताया कि अभयारण्य से भटककर शहरी क्षेत्र में जाने वाले तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगाने से यह जानकारी भी मिल सकेगी कि तेंदुआ कहां से निकलता है, वापस जंगल की तरफ कब जाता है। प्रयोग सफल होने पर आबादी वाले इलाकों के समीप विचरण करने वाले अन्य तेंदुओं को भी रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे।

वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि राजस्थान में पहली बार तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगाए जा रहे हैं। यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य संवेदनशील वन क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। वन अधिकारियों ने बताया कि रेडियो कॉलर लगाने से यह पता चल सकेगा कि तेंदुए का प्राकृतिक आवास कितना बड़ा है। जंगल के कितने बड़े क्षेत्र में उसकी गतिविधि रहती है। उन्होंने बताया कि रेडियो कॉलर लगने के बाद तेंदुओं की हर गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। जैसे ही कोई तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, अलर्ट सिस्टम के जरिए क्षेत्र के कर्मी को तुरंत सूचना मिल जाएगी। इससे समय रहते बचाव, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा संबंधी कदम उठाए जा सकेंगे।

युवा मेहनत करें, राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा तरुणाई राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है। युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा का उपयोग कर देश दुनिया में सिरमौर बन सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने युवाओं से अपील की है कि वे मेहनत करें, सरकार हर कदम पर साथ खड़ी है। शर्मा मंगलवार को मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग में वृहद राजस्थान की स्थापना की थी। इसीलिए हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री देश के किसान, युवा, महिला और मजदूर चारों वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने देश में विकास एवं गरीब कल्याण की योजनाओं से दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप से युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए मंच मिला है तथा उन्हें आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त हुए है।

शर्मा ने कहा कि बजट 2026-27 में भी युवाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। जनजाति क्षेत्र के 5 हजार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही, जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना तथा 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आईसीटी लैब बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद योजना के माध्यम से जिले की स्थानीय विशिष्टताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के प्रयासों को सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। हमारी सरकार द्वारा पानी जैसी बुनियादी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी, गंगनहर, माही सहित परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश में बिजली तंत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। राजस्थान में अभी कृषि क्षेत्र में 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है, 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली देने के लिए हम संकल्पित हैं।

शर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए हमारी सरकार युवा नीति लाई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता बनें। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपरलीक जैसे प्रकरणों से युवाओं के सपने चूर-चूर हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपरलीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एसआईटी का गठन कर कड़ी कार्रवाई की गई है और अब तक 420 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को 4 लाख सरकारी क्षेत्र में एवं 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख 33 हजार भर्ती प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। सरकार के प्रयासों से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और पेपरलीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निवेश और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग

मुस्लिम विधायकों के फैसले पर उठे सवाल

बाल मुकुंद जोशी
dakshinbharat.com

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, जिससे इस मुद्दे को लेकर सामाजिक और नैतिक बहस भी तेज हो गई है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की क्रॉस वोटिंग न केवल पार्टी अनुशासन पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है।

जयपुर। राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। खास तौर पर उन मुस्लिम विधायकों के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस में अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व की बात करते रहे हैं, लेकिन मतदान के समय उनके रुख ने भाजपा को सीधा लाभ पहुंचाया।

ओडिशा की बाराबती सीट से निर्वाचित विधायक सोफिया फिरदौस, जिन्हें प्रदेश की पहली मुस्लिम महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है, का नाम इस सूची में प्रमुखता से सामने आया है। उनके अलावा हरियाणा के पुन्हाना से विधायक चौधरी इलियास और हथीन से विधायक मोहम्मद इजरायल ने भी कथित तौर पर पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, जिससे इस मुद्दे को लेकर सामाजिक और नैतिक बहस भी तेज हो गई है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की क्रॉस वोटिंग न केवल पार्टी अनुशासन पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है।

दिलचस्प पहलू यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में संकोच बरतने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा भाजपा के पक्ष में गया वोट राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को लेकर कई तरह के संकेत देता है। फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी राजनीति में निष्ठा, रणनीति और अवसरवाद के बीच की रेखाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं।

सामाजिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने का कार्य कर रहा है आरएसएस : रमेशचंद्र अग्रवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता रमेशचंद्र अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि संगठन ने पिछले वर्ष में उल्लेखनीय विस्तार किया है और दैनिक शाखाओं की संख्या लगभग 6,000 बढ़कर 88,000 से अधिक हो गई है, जबकि देशभर में गतिविधियों के आयोजन स्थलों की संख्या बढ़कर 55,000 से अधिक हो गई है।उन्होंने बताया कि अब आरएसएस की गतिविधियां दूरदराज़ के क्षेत्रों तक पहुंच चुकी हैं, जिनमें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख समेत आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां नियमित शाखाएं संचालित की जा रही हैं। अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में 12,109 शाखाएं और 5,950 साप्ताहिक सभाएं आयोजित होती हैं और समाज में पहुंच बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 13 से 15 मार्च तक हरियाणा के समालखा में तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक सद्भाव व राष्ट्र निर्माण में समाज की अधिक भागीदारी पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। अग्रवाल ने कहा कि संगठनात्मक विस्तार के साथ-साथ आरएसएस पंच परिवर्तन पहल के माध्यम से सामाजिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने का कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि आरएसएस अगले वर्ष देशभर में 96 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगा, जो इसके नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस ने हिंदू परिवारों में बच्चों की संख्या को लेकर सरकार के लिए कोई प्रस्ताव दिया है तो उन्होंने कहा कि संघ का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि संघ प्रमुख ने वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ कहा है कि परिवारों में आदर्श रूप से कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। आरएसएस नेता ने कहा, बच्चों का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास तब बेहतर होता है जब वे अन्य बच्चों के बीच बड़े होते हैं। हिंदू परिवारों में कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए।

सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हनुमानगढ़ । राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से आज सुबह एक हृदयविदारक खबर सामने आई है। रावतसर क्षेत्र के पास मेगा हाईवे पर एक निजी बस और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। सुबह 7 बजे बरमसर के पास हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, यह भीषण दुर्घटना मंगलवार सुबह करीब 7:00 बजे रावतसर क्षेत्र के बरमसर के पास घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार बस और ट्रक की सीधी टक्कर हुई, जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी।

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सुभाष गोदारा और थाना प्रभारी ईश्वरानन्द पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुँचाया गया।

अस्पताल में भर्ती घायलों में से 5 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल (हनुमानगढ़) रेफर कर दिया गया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम संजय कुमार और नितेश मोची ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को उचित उपचार के निर्देश दिए।पुलिस ने मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। दुर्घटना के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाईवे पर यातायात को सुचारू करने के लिए क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर दुख जताते हुए लिखा- हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र में बरमसर के पास मेगा हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 5 व्यक्तियों की मृत्यु होना बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं उनके शोकाकुल परिजनों को धैर्य तथा हिम्मत प्रदान करें। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

बजट घोषणाओं को समय पर और पारदर्शिता के साथ लागू करें : दिलावर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन पंचायती राज विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस दौरान पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी भी उपस्थित रहे। दिलावर ने बैठक में बजट घोषणा और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी बजट घोषणाओं को समय पर और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आमजन से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। मंदिरों को पट्टे वितरण, जन समस्या समाधान शिविर, पंचायतों की नियमित मॉनिटरिंग और ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही घुमंतु परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

दिलावर ने नई पंचायतों के लिए भूमि एवं भवन की व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, जल संरक्षण, स्वच्छता और पॉलिथीन पर रोक जैसे विषयों पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने वर्ष 2013 में जिला परिषदों द्वारा ली गई लिपिक भर्ती को एक सप्ताह में एसओजी को भेजने के निर्देश दिए।

आत्मनिर्भर बनाने में विश्वविद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण : राज्यपाल

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को कहा कि आज के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बागड़े ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय स्वदेशी सोच और नवाचार को बढ़ावा दें, तो भारत वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकता है। राज्यपाल बागड़े उदयपुर में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयु) की 'वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26' के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। जारी एक बयान के अनुसार इस दो दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु (वाइस चांसलर) भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी राष्ट्रवाद और आर्थिक देशभक्ति जैसे विचार केवल नारे नहीं बल्कि व्यवहार में उतारे जाने वाले संकल्प हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से आह्वान किया कि वे शोध, नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार सृजन की दिशा में सक्षम बनाएं।

दुर्लभ कैराकल की हत्या कर शव जलाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले में कैराकल यानी दुर्लभ जंगली बिल्ली को मारकर उसे जलाने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद वन विभाग हरकत में आया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मौके से कैराकल का अधजला शव बरामद किया है। वन विभाग के अनुसार यह घटना भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे शाहगढ़ क्षेत्र की है। जहां दो दिन पहले कैराकल को मारकर लकड़ियों के ढेर पर रखकर जला दिया गया था। मृत दुर्लभ वन्यजीव कैराकल बिल्ली के वीडियो वायरल होने की घटना को उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने गंभीरता से लेते हुए सहायक वन संरक्षक मुख्यालय जैसलमेर दिलीप सिंह राठौड़ के निर्देशन में टीम का गठन किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी सम लक्ष्मणसिंह भाटी और क्षेत्रीय वन अधिकारी जैसलमेर पूनम सिंह के नेतृत्व में जांच प्रारम्भ की गई। जांच में घटनास्थल व आरोपियों की पहचान की गई।

उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहगढ़ निवासी इब्राहिम खान (32), उमा (31) और सलिदाद (50) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि तीनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है, जिसका उपयोग घटना के दौरान किया गया था।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दो दिन पहले किसी जंगली जानवर ने उनके करीब 50 मवेशियों को मार दिया था। इस वजह से उन्होंने उस जानवर के पैरों के निशान का पीछा करना शुरू किया। उप वन संरक्षक ने बताया कि आरोपियों के अनुसार जब उन्हें जंगली बिल्ली दिखाई दी तो वे उसके पीछे दौड़ पड़े। आरोपियों का कहना है कि लगातार पीछा करने के दौरान बिल्ली भागते-भागते खुद ही मर गई। हालांकि वन विभाग इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैराकल की मौत वास्तव में किस परिस्थिति में हुई।

नया विक्षोभ आज से होगा सक्रिय, आंधी बारिश के आसार

जयपुर। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बुधवार से शुरू होगा जिससे कई इलाकों में बारिश होने व आंधी आने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 18-21 मार्च के दौरान सक्रिय होगा। इसके असर से कहीं कहीं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने व बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके असर से 18 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने तथा शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।

नीतीश कुमार ने 171 करोड़ रुपए की 88 योजनाओं का किया उद्‍घाटन एव शिलान्यास, विपक्ष पर साधा निशाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भागलपुर/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दौरान भागलपुर जिले के जगदीशपुर स्थित बैजानी पंचायत में 171 करोड़ रुपए की लागत से 88 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्‍घाटन और शिलान्यास किया।

कुमार ने इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कुमार ने भागलपुर-बौंसी रेल लाइन पर निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले राज्य में 'जंगलराज' की स्थिति थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उस समय लोग शाम के बाद घर से निकलने में डरते थे और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं, जबकि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी अत्यंत खराब थी। कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई और बाद में मंदिरों की भी चहारदीवारी कराई गई, जिससे भूमि विवाद समाप्त हुए और प्रदेश में शांति कायम हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गांवों को सड़कों और पुल-पुलियों के माध्यम से शहरों से जोड़ा गया है, जिससे आवागमन में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई है और अब सरकार छतों पर मुफ्त सौर पैनल लगाने की योजना भी चला रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया है तथा आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास में लगातार सहयोग कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में विकास को और गति मिलेगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, जिले के विधायक, जदयू के जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बच्चों की तस्करी करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार, छह बच्चे छुड़ाये गए

चंदौली (उप्र)/भाषा। चंदौली जिले के दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और 'बचपन बचाओ आंदोलन' की एक संयुक्त टीम ने छह नाबालिग बच्चों को एक मानव तस्कर से बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इन बच्चों को उनके माता-पिता को पैसे का लालच देकर मजदूरी के लिए ट्रेन से ले जाया जा रहा था। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक प्रदीप रावत ने बताया कि सोमवार शाम जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर ट्रेन नंबर 22948 (भागलपुर-सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस) के नियमित निरीक्षण के दौरान जनरल कोच में बच्चों को साथ ले जा रहे दिनेश मंडल नामक आरोपी को पकड़ा गया। रावत ने कहा कि पूछताछ करने पर, बच्चों और तस्कर दोनों ने खुद को झारखंड के गोड्डा जिले का निवासी बताया।

ईद का जश्न मनाने की अपील पर बोले मौलाना फरंगी महली : कहा- ईद का संबंध किसी इंसानी घटना से नहीं

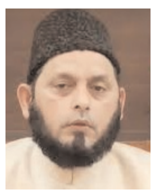

लखनऊ/भाषा। ईरान पर हमले के विरोध में भारत में कुछ स्थानों पर ईद का जश्न ना मनाने और बांह पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने की अपीलों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इससे असहमति जताते हुए मंगलवार को कहा कि ईद रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है और इसका संबंध किसी एक इंसानी घटना से नहीं है। मौलाना खालिद रशीद ने ईद-उल-फित्र की तैयारियों के संबंध में ईदगाह लखनऊ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में ईरान पर हमले के विरोध में ईद का जश्न नहीं मनाने और बांह पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करने की अपीलों का संदर्भ लेते हुए कहा कि ईद का संबंध किसी एक इंसानी घटना से नहीं है। उन्होंने अपने बयान के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि दूसरी हिजरी (इस्लामी संवत) में 17 रमजान को गजवा-ए-बद्र (बद्र के मैदान में हुई लड़ाई) हुआ, उसके बाद भी ईद मनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 21 रमजान 40 हिजरी को हजरत अली की शहादत हुई और 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हुआ मगर उसके बावजूद उस साल भी मुसलमानों ने ईद मनाई थी।

वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर बिरयानी खाने के आरोप में 14 गिरफ्तार

वाराणसी (उप्र)/भाषा। वाराणसी पुलिस आयुक्तालय के कोतवाली क्षेत्र में गंगा में नाव पर इफ्तार करने और कथित रूप से बिरयानी खाने का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोतवाली के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें गंगा में नाव पर बैठकर कुछ लोग इफ्तार पार्टी करते दिखे। उन्होंने बताया कि वीडियो में यह प्रतीत हो रहा है कि पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसीपी ने बताया कि मामले में कार्रवाई के लिए एक टीम बनाई गई और इसके बाद इफ्तार पार्टी में कथित तौर पर शामिल 14 लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

भाजपा बंगाल में सीटें जीतने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही : स्वपन दासगुप्ता

कोलकाता/भाषा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दक्षिण कोलकाता के रासबिहारी से भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता का नामांकन एक तरह से घर वापसी जैसा है। नफील्ड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड के विद्वान, स्तंभकार और हिंदुत्व राष्ट्रवाद के विचारक दासगुप्ता मानते हैं कि उनकी स्पष्ट रूप से शहरी छवि उन्हें रासबिहारी सीट के लिए और अधिक उपयुक्त बनाती है। यह वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां उनका और उनके विस्तारित परिवार का निवास है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व राज्यसभा सदस्य ने 2021 के विधानसभा चुनावों में ग्रामीण तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं पाए और अपने निकटतम टीएमसी प्रतिद्वंद्वी से 7,000 से कुछ अधिक वोटों के अंतर से हार गए। दासगुप्ता ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, ''रासबिहारी मेरे लिए घर की सीट जैसी है। यह एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसकी सीमाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है। यहां कोलकाता के कुछ सबसे संपन्न लोगों के साथ-साथ शहर के सबसे गरीब तबके के लोग भी रहते हैं, जिससे यह इलाका काफी विविधतापूर्ण है।

धोनी शीर्ष छह में बल्लेबाजी करें या फिर हट जाएं: डिविलियर्स

नई दिल्ली/भाषा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने मंगलवार को बेबाक राय देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को आगामी आईपीएल में शीर्ष छह में बल्लेबाजी करनी चाहिए क्योंकि आठवें या नौवें नंबर पर आने से उनकी मौजूदगी के साथ न्याय नहीं होता। धोनी 44 साल के हो चुके हैं और 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी सीएसके के लिए खेलेंगे और डिविलियर्स ने इस करिश्माई खिलाड़ी से पिछले कुछ वर्षों में बल्लेबाजी क्रम में बहुत नीचे खेलने की रणनीति को बदलने की अपील की। आईपीएल सत्र में सीएसके में धोनी की भूमिका पर बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा, ''यह मुश्किल है और सीधा-सीधा मामला नहीं है। ब्रांड बनने में वर्षों लगते हैं और सीएसके ने धोनी की शख्सियत के साथ कई वर्षों में यह साम्राज्य खड़ा किया है जो हमेशा से वहां मौजूद रहे हैं। जब आप सीएसके का नाम लेते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में धोनी का नाम आता है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी भूमिका पूरी तरह से उस ब्रांड को जितना हो सके उतना मजबूत बनाए रखने की रही है। इसीलिए मुझे आठ या नौ नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती और ना ही वह पिछले सत्र की तरह कुछ खास कर पा रहे हैं।''

जयराम रमेश ने स्वेज सकंट के समय कृष्णा मेनन के कूटनीतिक प्रयास को याद किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच मंगलवार को 1950 के दशक के स्वेज संकट का उल्लेख किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र में उस वक्त के भारतीय प्रतिनिधि वीके कृष्ण मेनन ने इस मामले के समाधान के लिए किए गए कूटनीतिक प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वर्ष 1956 में पहले इसरायल तथा बाद में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिस्र पर किया गया आक्रमण स्वेज संकट के नाम से जाना जाता है। यह आक्रमण स्वेज नहर पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण पुनः स्थापित करने तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से किया गया था।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, दुनिया होर्मुज जलडमरूमध्य संकट से जूझ रही है। 70 साल पहले, यह उस समस्या से जूझ रहा था जिसे स्वेज़ संकट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, 26 जुलाई 1956 को मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पश्चिम में भारी हंगामा मच गया और युद्ध के बादल मंडराने लगे। संकट को सुलझाने के कूटनीतिक प्रयास के केंद्र में जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं बल्कि वीके कृष्ण मेनन थे। वह सराहनीय रूप से सफल हुए लेकिन केवल कुछ समय के लिए।

उनके मुताबिक, 29 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल ने मिस्र पर आक्रमण शुरू किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के हस्तक्षेप के बाद उन्हें कुछ ही दिनों में अपमानजनक तरीके से इस अभियान को रद्द करना पड़ा। रमेश का कहना था, विडंबना यह है कि यह वही व्यक्ति था जिसने तीन साल पहले ईरान के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसद्दिक़ को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका-ब्रिटेन के संयुक्त अभियान को मंजूरी दी थी, जिन्होंने वहां तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था।

देवेगौड़ा को सोनिया का जवाबः आपकी चिंताओं का संज्ञान लिया

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जवाबी पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने संसद के अंदर व्यवधान और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी उनकी चिंताओं का संज्ञान लिया है। सोनिया गांधी ने उगादी पर्व की पूर्व संध्या पर देवेगौड़ा को शुभकामनाएं भी दीं।

सोनिया गांधी को संबोधित पत्र में देवेगौड़ा ने सोमवार को कहा था कि संसद और उसके परिसर में ''बिना सोचे-समझे, जो अराजकता फैलाई गई है, उससे वह बहुत परेशान हैं। यह अराजकता मुख्य रूप से विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई है।'' जनता दल (सेक्युलर) के नेता ने कहा, ''मुझे दृढ़ता से लगता है कि विपक्ष के नेता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद के अंदर व उसके परिसर में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न किया है।''

भाजपा ने आरएसएस, रॉ पर प्रतिबंध की मांग ठुकराई, कहा : कांग्रेस की राष्ट्र-विरोधी ताकतों से मिलीभगत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) की उस रिपोर्ट को 'निराधार' बताया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और 'रिसर्च एनालिसिस विंग' (रॉ) पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट का समर्थन करके भारत के खिलाफ रुख अपनाया है।

सत्तारूढ़ दल ने कहा कि केंद्र ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और बताया कि इसमें 'वस्तुनिष्ठ तथ्य' नहीं हैं तथा यह विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित नहीं है। भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, ''इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट में कोई वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं हैं। वास्तव में, सरकार ने अमेरिकी आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।'' उन्होंने यह भी कहा, ''यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते-करते कांग्रेस पार्टी आज खुद भारत के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है।'' पात्रा ने कहा कि कोई भी विदेशी आयोग भारत को आदेश नहीं दे सकता या उसके संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, ''कोई आयोग भारत से नहीं कह सकता कि रॉ पर प्रतिबंध लगाए। सरकार ने इसका कड़ा जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस रॉ के खिलाफ बोल रही है और इस आयोग के साथ खड़ी है।''

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर भारत को बदनाम करने के प्रयास का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया गया है। उन्होंने (कांग्रेस ने) कहा है कि अमेरिका और इस एजेंसी ने जो (कुछ) कहा है, वह सही है। पार्टी राहुल गांधी के आदेश पर भारत को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।''

ममता बनर्जी ने ईद से पहले अधिकारियों के तबादलों पर सवाल उठाए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि राज्य में किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में निर्वाचन आयोग और भाजपा जिम्मेदार होंगे।

विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते हुए पत्रकारों से बातचीत में बनर्जी ने ईद से ठीक पहले प्रमुख प्रशासनिक पदों पर किए गए परिवर्तनों के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ''ईद से ठीक पहले वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला क्यों किया जा रहा है? क्या चुनाव से पहले दंगे भड़काने का कोई इरादा है?

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तबादलों की सूची भाजपा कार्यालय में तैयार की गई और निर्वाचन आयोग ने केवल इसे लागू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के बाहर के कुछ अधिकारियों को भाजपा को चुनावी प्रक्रिया में सहायता देने के लिए लाया गया है। बनर्जी ने कहा, भाजपा की मदद के लिए राज्य के बाहर से कुछ लोगों को लाया गया है।

निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा कि आयोग भाजपा की ओर से अच्छा खेल खेल रहा है। बनर्जी ने कहा, उन्हें सीधे भाजपा के लिए प्रचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया, अधिकारियों को इसलिए बदला गया है, ताकि बिना किसी बाधा के भाजपा को धन और हथियार आसानी से हस्तांतरित किए जा सकें। चुनाव अवधि के दौरान किसी भी घटना के होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए बनर्जी ने कहा कि इसके लिए भाजपा और निर्वाचन आयोग दोनों को जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर कुछ अप्रिय घटना घटती है, तो भाजपा और निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होंगे। अगर कुछ गलत होता है, तो उन्हें जवाबदेह होना चाहिए।

टीएमसी प्रमुख ने राज्य में भाजपा के राजनीतिक प्रचार अभियान पर भी हमला किया और पार्टी पर उनकी सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा का तबादला कर दिया। इसके बाद, आयोग ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पीयूष पांडे और कोलकाता के मुख्य सचिव सुप्रतिम सरकार को भी पद से हटा दिया।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। मतगणना चार मई को होगी।

अफगानिस्तान में पाक की बर्बरता को विश्व स्तर पर खारिज किया जाना चाहिएः कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल पर पाकिस्तान के हवाई हमले की मंगलवार को निंदा की और कहा कि इस तरह की बर्बरता को विश्व स्तर पर दृढ़ता से खारिज किया जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस अफगानिस्तान के उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है। उन्होंने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, ''हम काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले के बाद जानमाल की भीषण क्षति से बहुत व्यथित हैं। इसमें लगभग 400 लोग मारे गए।'' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''हम मानवता के खिलाफ ऐसे कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की बर्बरता को विश्व स्तर पर दृढ़ता से खारिज किया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''भारत, अफगानिस्तान के लोगों के साथ लंबे समय से मित्रता और सद्भावना का रिश्ता साझा करता है। इस कठिन क्षण में, हम अफगान पड़ोसियों के साथ सहानुभूति जताते हैं और उनके राष्ट्र के लिए शांति और स्थिरता की कामना करते हैं।''

केसी त्यागी ने जदयू से नाता तोड़ा, कहा- भविष्य को लेकर जल्द फैसला करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

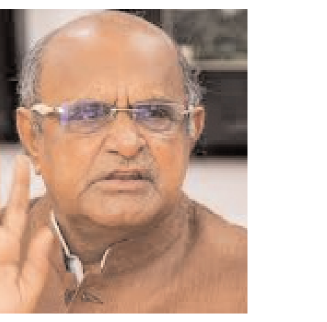

नई दिल्ली/भाषा। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अपने भविष्य के कदम को लेकर जल्द फैसला करेंगे।

त्यागी समता पार्टी और जनता दल के विलय से अक्टूबर 2003 में अस्तित्व में आई पार्टी जदयू से जुड़े हुए थे। उन्होंने जदयू में मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया था।

त्यागी (75) ने 'पीटीआई-भाषा' के एक सवाल पर बताया, ''हां, मैंने पार्टी छोड़ दी है।''

पूर्व राज्यसभा सदस्य ने एक बयान में कहा, ''पार्टी का सदस्यता अभियान समाप्त हो गया है। इस बार मैंने पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है।'' उन्होंने हालांकि रेखांकित किया कि समाज के वंचित वर्गों सहित दलितों, किसानों और कृषि श्रमिकों के हितों से संबंधित ''व्यापक वैचारिक मुद्दों'' के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ''पहले की तरह ही दृढ़'' है। त्यागी ने कहा, ''लगभग आधी सदी तक मेरे साथी रहे नीतीश कुमार के प्रति मेरा व्यक्तिगत सम्मान अब भी अपरिवर्तित है।'' उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक लोगों से परामर्श करने के बाद जल्द ही भविष्य को लेकर फैसला किया जाएगा।

त्यागी ने कहा,''मेरे कुछ राजनीतिक मित्र, समर्थक और कार्यकर्ता 22 मार्च 2026 को मावलंकर हॉल, रफी मार्ग में देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं।''

अनुभवी समाजवादी नेता ने कहा, ''हम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेते रहेंगे।''

पढ़ाई में तो अच्छे नंबर नहीं मिले, लेकिन क्रिकेट में 80 प्रतिशत अंक हासिल किएः सूर्यकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सूर्यकुमार यादव को भले ही पढ़ाई में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने आखिरकार 80 प्रतिशत अंक हासिल कर लिए हैं।

सूर्यकुमार की अगुवाई में भारत ने हाल में टी20 विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत का भरपूर आनंद ले रहे सूर्यकुमार का भारतीय कप्तान के रूप में जीत का रिकॉर्ड 80 प्रतिशत है। मुंबई के रहने वाले सूर्यकुमार स्वाभाविक रूप से अपने इन आंकड़ों से बेहद खुश थे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करते समय वह कभी इतने अधिक नंबर लेकर नहीं आए थे। सूर्यकुमार ने 2024 में टी20 कप्तान का पद संभालने के बाद लगातार सफलता हासिल की। उनकी अगुवाई में भारत ने अभी तक जो 52 मैच खेले हैं उनमें से 42 मैच में उसे जीत मिली है। सूर्यकुमार ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ''मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज में मैंने जो प्रतिशत हासिल करने की कोशिश की वह अब मुझे क्रिकेट में मिल रही है।'' उन्होंने कहा, ''वहां (स्कूल या कॉलेज में) मैं कभी 50-60 प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। लेकिन यह (जीत की दर 80 प्रतिशत) सुनकर वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे आंकड़ों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करता हूं लेकिन किसी को भी किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं होता और मुझे भी जीतना पसंद है।'' सूर्यकुमार के पिता अशोक कुमार यादव भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। लेकिन सूर्यकुमार का कभी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा और उनके परिवार ने क्रिकेट में उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरा सहयोग दिया।

मंधाना महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार, हरमनप्रीत सातवें स्थान पर पहुंची

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/भाषा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी महिला एकदिवसीय रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ सातवें पायदान पर पहुंच गई हैं, जबकि उपकप्तान स्मृति मंधाना शीर्ष स्थान पर कायम हैं। रैंकिंग में यह बदलाव न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सोफी डिवाइन के दो स्थान फिसलकर नौवें नंबर पर आने के बाद हुआ। भारत की जेमिमा रोड्रिग्स 12वें स्थान पर बरकरार हैं।

न्यूजीलैंड की बल्लेबाज मैडी ग्रीन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 'आईसीसी महिला चैंपियनशिप सीरीज' के अंतिम मैच में 94 रनों की शानदार पारी खेलकर रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। 33 वर्षीय ग्रीन की डुनेडीन में खेली गई 73 गेंदों की पारी की बदौलत उनकी टीम ने 200 रन से जीत दर्ज करते हुए श्रृंखला में 3-0 से सूपड़ा साफ किया। इस प्रदर्शन से वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर 610 रेटिंग अंकों के साथ 17वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। न्यूजीलैंड की हरफनमौला अमेलिया केर ने आखिरी वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 रन बनाने के साथ 22 रन देकर पांच विकेट झटके और 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार नाम किया। इस हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया। इस प्रदर्शन से केर 21वें स्थान से संयुक्त 19वें स्थान पर पहुंच गई हैं और बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी दोनों में 600 से अधिक रेटिंग अंक हासिल किए हैं।

सुविचार

दूसरों से उम्मीदें रखना दुखों का कारण है। खुद पर भरोसा रखें और अपनी खुशी की चाबी दूसरों को न सौंपें।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

पाक को ऐसे करें बेनकाब

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के दमन का मुद्दा संरा महासभा में उठाकर इस पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान हर मंच पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए मानवाधिकारों का उपदेश देता है, लेकिन अपने नागरिकों का उत्पीड़न करता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं से ज्यादा नफरत अहमदिया समुदाय से की जाती है। उन्हें परेशान करने के लिए सरकार और कट्टरपंथी संगठन नए-नए बहाने ढूंढ़ते रहते हैं। इस वजह से अहमदिया समुदाय के लोग अपनी पहचान छिपाने को मजबूर हैं। नफरत की इस सूची में अहमदिया से भी ऊपर यहूदियों का नंबर आता है। ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तानियों ने अपने देश में शायद ही किसी यहूदी को देखा होगा। किसी को याद नहीं होगा कि कब उनका कोई पड़ोसी यहूदी था! इसके बावजूद यहूदियों से खूब नफरत की जाती है। पाकिस्तान की सरकारों, नेताओं, सेना, एजेंसियों और कट्टरपंथियों ने यहूदियों को लेकर मन में इतना जहर भर दिया है कि आम पाकिस्तानी उन्हें अपना जन्मजात दुश्मन समझता है। जब नफरत का बीज बोया जाता है तो वही फल मिलता है, जो आज पाकिस्तान को मिल रहा है। चूंकि यहूदी पाकिस्तान में हैं नहीं, इसलिए कट्टरपंथी ताकतें कभी हिंदुओं को, तो कभी अहमदियों को निशाना बनाती रहती हैं। पिछले साल अप्रैल में कराची में एक उग्र भीड़ ने अहमदिया समुदाय के उपासना स्थल पर हमला किया और एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। उस वारदात में टीएलपी नामक कट्टरपंथी संगठन का हाथ बताया गया था।

पिछले साल मई में एक मशहूर डॉक्टर, जो सरगोधा में अपना अस्पताल चलाते थे, को गोली मार दी गई थी। वजह थी- डॉक्टर अहमदिया समुदाय से थे। अक्टूबर में एक और अहमदिया उपासना स्थल पर तीन बंदूकधारियों ने हमला किया था। इससे कई लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में अक्सर अहमदिया लोगों के खिलाफ झूठे आरोपों में एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। किसी को पुरानी दुश्मनी निकालनी हो, जमीन हड़पनी हो, फलते-फूलते व्यापार को बर्बाद करना हो, तो अहमदिया और हिंदू सबसे आसान शिकार होते हैं। झूठी शिकायत करने वालों को पुलिस का पूरा साथ मिलता है। पाकिस्तानी समाज में यह नफरत किस कदर फैल चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जनरल क़मर जावेद बाजवा सेना प्रमुख बने थे तो उनके प्रतिद्वंद्वियों ने यह अफवाह फैला दी थी कि वे अहमदिया समुदाय से आते हैं। इससे वहां भारी हंगामा खड़ा हो गया था। लोग उन्हें सेना प्रमुख के पद पर नहीं देखना चाहते थे। बाद में बाजवा ने धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि वे अहमदिया नहीं हैं, तब जाकर मामला शांत हुआ। जब इमरान ख़ान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक सुधारों और नीतिनिर्माण के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया था। उसमें उन्होंने एक मशहूर अर्थशास्त्री आतिफ को भी शामिल किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति से कट्टरपंथी भड़क उठे थे। प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के इन प्रोफेसर को सिर्फ इस वजह से हटना पड़ा, क्योंकि वे अहमदिया समुदाय से हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार की स्थिरता के लिए है। इसके बाद कुछ अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस पर कई पाकिस्तानियों ने खुशी मनाई थी। उन्हें यह मंजूर है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका से लेकर चीन तक हाथ फैलाएं, लेकिन वे किसी अहमदिया को सलाहकार के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वह कितना ही बड़ा विशेषज्ञ हो। पाकिस्तान जिस मंच पर भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करे, यह मुद्दा उठाकर उसे बेनकाब करना चाहिए। पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के पास कोई जवाब नहीं होगा।

ट्वीटर टॉक

ग्राम- मोरोड़ी निवासी सीआरपीएफ में उपनिरीक्षक मोहन सिंह गुर्जर के निधन का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। मैं, ईश्वर से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।

-राज्यवर्धनसिंह राठौड़

राज्यसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को विजय पर हार्दिक बधाई । आपके सफल और उज्वल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। साथ ही एनडीए के सभी नवनिर्वाचित प्रत्याशियों को भी विजय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!

-वसुंधरा राजे

विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की अंबाबाड़ी सब्जी मंडी-नाले-पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क एवं एमआईसी सेंटर का जेडीसी श्री सिद्धार्थ महाजन जी, नगर निगम के सीईओ श्री गौरव सैनी जी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

-दिया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

मोह की माया

एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से पूछा कि भगवान विष्णु की माया कैसी है। धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा शांत करने के लिए श्रीकृष्ण ने उन्हें देवर्षि नारद का प्रसंग सुनाया। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से उनकी माया देखने का हठ किया। तब भगवान उन्हें एक सरोवर के पास ले गए और स्नान करने का निर्देश दिया। सरोवर में डुबकी लगाते ही नारद जी का स्वरूप बदल गया और वे एक अत्यंत रूपवती स्त्री बन गए। तभी वहां से गुजर रहे राजा तालध्वज उस सुंदरी पर मुग्ध हो गए और उनसे विवाह कर लिया। वर्षों बीत गए; महल सुख-समृद्धि से भर गया, संतानें हुईं और परिवार का विस्तार हुआ। नारद पूर्णतः मोह-माया में लिप्त हो गए। किंतु समय के क्रूर चक्र ने स्थिति बदल दी। सत्ता और लालच के कारण उनके विशाल वंश में भीषण युद्ध हुआ और उनके सभी पुत्र-पौत्र मारे गए। अपने परिवार के विनाश पर रानी बनी नारद विलाप करने लगीं। तब भगवान ने एक ब्राह्मण का वेष धरकर उन्हें समझाया कि यह सब विष्णु की माया है। उन्होंने नारद को पुनः उसी सरोवर में स्नान कराया। बाहर निकलते ही नारद अपने वास्तविक मुनि स्वरूप में आ गए।

सामयिक

पश्चिम एशिया की समकालीन परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि सैन्य हस्तक्षेप कई बार समस्या को हल करने के बजाय उसे और जटिल बना देता है। इससे क्षेत्रीय असुरक्षा बढ़ सकती है, अविश्वास गहरा सकता है और अन्य देशों को भी परमाणु हथियार विकसित करने की प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए परमाणु प्रसार की चुनौती से निपटने के लिए दीर्घकालिक और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें कूटनीति, सहयोग और वैश्विक संस्थागत ढाँचे की केंद्रीय भूमिका हो। यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में गंभीर है, तो उसे यह समझना होगा कि परमाणु प्रसार जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि संवाद, विश्वास और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था से ही संभव है।

परमाणु प्रसार पर अंकुश या उसे तेज करने की भूल?

डॉ. सत्यवान सौरभ
मोबाइल :9466526148

परमाणु हथियारों का प्रसार आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि परमाणु हथियारों का विस्तार सीमित रखा जाए और नए देशों को इस श्रेणी में प्रवेश करने से रोका जाए। इसी उद्देश्य से अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियाँ, निगरानी तंत्र और कूटनीतिक पहलें अस्तित्व में आईं। इसके बावजूद समय-समय पर यह विचार सामने आता रहा है कि यदि किसी देश के परमाणु कार्यक्रम से वैश्विक या क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा हो, तो उसे रोकने के लिए निवारक या पूर्व-शार्लीश युद्ध का सहारा लिया जा सकता है। परंतु आलोचकों का तर्क है कि इस प्रकार के सैन्य हस्तक्षेप कई बार उस समस्या को हल करने के बजाय और जटिल बना देते हैं, क्योंकि वे अन्य देशों को भी परमाणु हथियार हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में हाल के दशकों की घटनाएँ इस बहस को और अधिक प्रासंगिक बनाती हैं। निवारक युद्ध की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि संभावित खतरे को उसके पूर्ण रूप लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। यदि किसी देश के पास परमाणु हथियार बनने की क्षमता विकसित हो रही है, तो कुछ शक्तियाँ यह मान सकती हैं कि सैन्य कार्रवाई करके उस कार्यक्रम को नष्ट कर देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। इस रणनीति का तर्क यह है कि यदि खतरे को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त कर दिया जाए, तो भविष्य में बड़े युद्ध या विनाश से बचा जा सकता है। परंतु व्यवहार में यह नीति कई बार अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती।

पश्चिम एशिया इस संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ लंबे समय से भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, धार्मिक-सांप्रदायिक तनाव, ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप जैसे अनेक कारक मौजूद हैं। इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों की संभावना को लेकर लगातार चिंता बनी रही है। कुछ देशों के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में संदेह और बहस दोनों रहे हैं। ऐसे माहौल में निवारक युद्ध या सैन्य कार्रवाई का विचार अक्सर चर्चा में आता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ संभावित परमाणु खतरे को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य यह था कि संबंधित देश के परमाणु बुनियादी ढाँचे को नष्ट करके उसे हथियार विकसित करने से रोका जाए। प्रारंभिक दृष्टि में यह रणनीति प्रभावी प्रतीत हो सकती है, क्योंकि इससे परमाणु कार्यक्रम को तत्काल नुकसान पहुँचता है। लेकिन दीर्घकालिक प्रभावों को देखें तो स्थिति अधिक जटिल दिखाई देती है। पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निवारक युद्ध किसी देश में असुरक्षा और अविश्वास की भावना को बढ़ा सकता है। यदि किसी राज्य को यह लगता है कि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को बाहरी शक्तियों से लगातार खतरा है, तो वह अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए अधिक आक्रामक कदम उठा सकता है। ऐसे में परमाणु हथियारों को अंतिम सुरक्षा गारंटी के रूप में देखा जाने लगता है। परिणामस्वरूप वह देश अपने परमाणु कार्यक्रम को और अधिक गुप्त तथा तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है।

दूसरा पहलू क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन से जुड़ा है। पश्चिम एशिया में कई देश एक-दूसरे के प्रति अविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। यदि किसी देश के खिलाफ निवारक सैन्य कार्रवाई होती है, तो अन्य देशों को भी यह आशंका हो सकती है कि भविष्य में उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इससे वे अपनी सुरक्षा नीति में परमाणु विकल्प को अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं। इस प्रकार एक देश के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरे क्षेत्र में परमाणु प्रसार की दौड़ को तेज कर सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक व्यवस्था से संबंधित है। निवारक युद्ध अक्सर विवादास्पद होता है, क्योंकि इसमें संभावित खतरे के आधार पर सैन्य कार्रवाई की जाती है, जबकि खतरा अभी पूरी तरह वास्तविक नहीं होता। यदि शक्तिशाली देश इस सिद्धांत को बार-बार लागू करते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर सकता है। अन्य देश भी अपने सुरक्षा हितों के नाम पर इसी प्रकार की कार्रवाइयों को उचित ठहराने लग सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर संघर्ष और अविश्वास बढ़ सकता है।

पश्चिम एशिया की समकालीन परिस्थितियों में यह बहस और भी जटिल हो जाती है। क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जो सुरक्षा चुनौतियों, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और बाहरी हस्तक्षेपों से घिरे हुए हैं। कुछ देशों के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहन निगरानी और कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। लेकिन समय-समय पर यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि यदि कूटनीति विफल हो जाती है, तो सैन्य विकल्प अपनाया जा सकता है। यही वह स्थिति है जहाँ यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या निवारक युद्ध वास्तव में समस्या का समाधान है। आलोचकों का कहना है कि सैन्य कार्रवाई अक्सर अल्पकालिक समाधान देती है, जबकि दीर्घकाल में वह समस्या को और गहरा कर सकती है।

जब किसी देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला होता है, तो इससे राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा की भावना को चोट पहुँचती है। इससे उस देश की जनता और राजनीतिक नेतृत्व में यह विश्वास मजबूत हो सकता है कि परमाणु हथियार ही बाहरी दबाव से बचने का सबसे प्रभावी साधन हैं। इस प्रकार निवारक युद्ध उस उद्देश्य के विपरीत परिणाम दे सकता है, जिसके लिए उसे किया गया था। इसके अलावा, आधुनिक समय में परमाणु कार्यक्रम केवल एक या दो स्थलों तक सीमित नहीं होते। वे कई संस्थानों, वैज्ञानिकों और तकनीकी क्षमताओं के व्यापक नेटवर्क पर आधारित होते हैं। इसलिए किसी एक प्रतिष्ठान को नष्ट करने से पूरे कार्यक्रम को समाप्त करना संभव नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि हमले के बाद संबंधित देश अपने कार्यक्रम को और अधिक सुरक्षित तथा गुप्त रूप से विकसित करने लगता है। इससे अंतरराष्ट्रीय निगरानी और नियंत्रण और कठिन हो जाते हैं।

हालाँकि यह भी सत्य है कि कुछ परिस्थितियों में निवारक कार्रवाई को सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक माना जाता है। यदि किसी राज्य के पास परमाणु हथियार बनने की क्षमता अत्यंत निकट हो और वह क्षेत्रीय या वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा हो, तो कुछ देश यह तर्क दे सकते हैं कि सैन्य हस्तक्षेप अपरिहार्य है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई को अंतिम विकल्प के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम व्यापक और अनिश्चित हो सकते हैं।

इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में भी गंभीर प्रयास करे। यदि केवल कुछ देशों के पास परमाणु हथियार बने रहें और अन्य देशों को उनसे दूर रहने के लिए कहा जाए, तो यह व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। वैश्विक स्तर पर समान और न्यायसंगत सुरक्षा व्यवस्था ही परमाणु प्रसार को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि निवारक युद्ध की रणनीति परमाणु प्रसार को रोकने का एक विवादास्पद और जोखिमपूर्ण तरीका है।

पश्चिम एशिया की समकालीन परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि सैन्य हस्तक्षेप कई बार समस्या को हल करने के बजाय उसे और जटिल बना देता है। इससे क्षेत्रीय असुरक्षा बढ़ सकती है, अविश्वास गहरा सकता है और अन्य देशों को भी परमाणु हथियार विकसित करने की प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए परमाणु प्रसार की चुनौती से निपटने के लिए दीर्घकालिक और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें कूटनीति, सहयोग और वैश्विक संस्थागत ढाँचे की केंद्रीय भूमिका हो। यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में गंभीर है, तो उसे यह समझना होगा कि परमाणु प्रसार जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि संवाद, विश्वास और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था से ही संभव है।

नजरिया

तपता मार्च, सूखता पानी : बदलते मौसम का खतरनाक संकेत

प्रो. आर.के. जैन अरिजीत

सुबह की हवा में अब वसंत की ठंडक नहीं, गर्मी की तीखी आहट है, और यही हाल कई शहरों में फैल चुका है। मार्च 2026 में दिल्ली में पारा 35.7ओउ तक पहुंचा – पहले सप्ताह का 50 साल का सबसे गर्म मार्च – जबकि गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 38-42ओउ तक पहुंच गया। लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहर भी इस असामान्य गर्मी की चपेट में हैं। यह क्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की स्पष्ट तस्वीर है जो पूरे देश की दिनचर्या में समा रही है। जो मार्च कभी हल्की धूप और सुकून का महीना था, अब तपिश और सूखेपन का अनुभव बन गया है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय की अनदेखी का नतीजा है, जिसे हम 'नया सामान्य' मानने लगे हैं। मार्च के शुरुआती दिनों में ही बढ़ती गर्मी ने मौसम की पुरानी धारणाएं तोड़ दी हैं। जो तपिश कभी अप्रैल-मई तक सीमित थी, वह अब पहले ही सप्ताह में रिकॉर्ड बना रही है। यह सिर्फ समय का बदलाव नहीं, बल्कि बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन का संकेत है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। चिंताजनक यह है कि पहाड़ी क्षेत्र भी अब इससे अछूते नहीं, साफ है कि जलवायु परिवर्तन सीमाएं पार कर चुका है। यह फैलता संकट हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमने प्रकृति से अपना संतुलन खो दिया है।

इस बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है। बड़े जलाशयों का घटता स्तर किसी सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव का नहीं, बल्कि गंभीर असंतुलन का संकेत है। मार्च में ही जब पानी आधा रह जाए, तो आने वाले महीनों का संकट साफ दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांवों में किसान फसलों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नदियां कमजोर पड़ रही हैं, भूजल नीचे जा रहा है और पानी की हर बूंद की अहमियत बढ़ती जा रही है। यह हालात स्पष्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल गर्मी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हमारे जल संसाधनों को भी तेजी से खत्म कर रहा है। तापमान और प्रदूषण का साथ इस संकट को और खतरनाक बना रहा है-एक ऐसा दोहरा प्रहार जो शरीर और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर रहा है। गर्मी बढ़ते ही हवा में मौजूद जहरीले कण और सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। दिल्ली और आसपास की खराब होती हवा यह दिखा रही है कि समस्या सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि उसी हवा की है जिस पर जीवन निर्भर है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों पर पड़ रहा है, और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ संकेत है कि यह अब पर्यावरण नहीं, गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

ऐसे हालात में वर्ल्ड बैंक का हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट (300 डॉलर मिलियन) राहत की उम्मीद जगाता है। साफ हवा के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि और उद्योग सुधार सकारात्मक कदम हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये पर्याप्त हैं, या हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से समस्या को संभाल रहे हैं? मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और कृषि सुधार जरूरी हैं, पर जब तक ये व्यापक और दीर्घकालिक नीति से नहीं जुड़ते, तब तक इनका असर सीमित ही रहेगा। वास्तविक चुनौती उन जड़ों पर प्रहार करने की है जहां से यह संकट पैदा हो रहा है। तेज औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों पर बढ़ती निर्भरता, जंगलों की कटाई और अव्यवस्थित शहरी विस्तार ने प्राकृतिक संतुलन को गहराई से बिगाड़ दिया है। फिर भी हम प्रदूषण को मौसमी मानकर टाल देते हैं और गर्मी को अस्थायी असुविधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मार्च 2026 ने साफ कर दिया है कि यह सोच अब खतरे से खाली नहीं। जब असामान्यता ही सामान्य लगने लगे, तो इसका मतलब है कि हमने समस्या को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उससे लड़ने की तैयारी अब भी अधूरी है।

इस बदलते दौर का सबसे भारी असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है, जहां रोजमर्रा अब सहज नहीं, संघर्ष बन गई है। एक साधारण परिवार के लिए पानी बचाना, बिजली संभालना और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना लगातार चुनौती है। बच्चों का बाहर खेलना घट गया है, बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा है और कामकाजी लोगों के लिए काम की गति बनाए रखना कठिन हो रहा है।

इस बदलते दौर का सबसे भारी असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है, जहां रोजमर्रा अब सहज नहीं, संघर्ष बन गई है। एक साधारण परिवार के लिए पानी बचाना, बिजली संभालना और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना लगातार चुनौती है। बच्चों का बाहर खेलना घट गया है, बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा है और कामकाजी लोगों के लिए काम की गति बनाए रखना कठिन हो रहा है। यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा कर रहा है- जहां साधन वाले खुद को बचा लेते हैं, वहीं कमजोर वर्ग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हम सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? लगातार चेतावनियां सामने हैं- बढ़ता तापमान, वैज्ञानिक रिपोर्टें, मौसम के संकेत- सब एक ही खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारी प्रतिक्रिया अक्सर सतही ही रहती है। हम तात्कालिक राहत के उपाय अपनाते हैं, जैसे ठंडक के लिए एसी या पानी का अस्थायी इंतजाम, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने से बचते हैं। यह सोच हमें कुछ समय जरूर दे सकती है, पर समस्या का हल नहीं। अब जरूरत है कि इस संकट को पूरी गंभीरता से स्वीकार कर ठोस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण को प्राथमिकता देना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और नीतियों में सख्ती लाना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुके हैं। साथ ही हर व्यक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर अब भी हम नहीं चेते, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा जाएगा। मार्च 2026 की यह तपिश केवल एक मौसम नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत है-अब तय हमें करना है कि हम इसे चेतावनी समझते हैं या अपनी नियति।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

शुभारंभ

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री चंद्र एस. पेम्मासानी ने नई दिल्ली में '24 स्पीड पोस्ट' सेवा का उद्घाटन किया। इस नई सेवा का उद्देश्य डाक वितरण प्रणाली को और अधिक तीव्र और आधुनिक बनाना है।

मोदी हैं राम और वैष्णव उनके हनुमान, जहां इशारा किया उस जगह को रेल से जोड़ दिया : तापिर गाव

नई दिल्ली/भाषा। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तापिर गाव ने मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ''जादूगर'' बताते हुए कहा कि ''प्रधानमंत्री मोदी 'राम' हैं तो वैष्णव उनके 'हनुमान' हैं।''

लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय संबंधी अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए अरुणाचल पूर्व संसदीय सीट से सदस्य गाव ने कहा कि आज पूर्वोत्तर के हर राज्य में या तो रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है या पहुंच रही है। उन्होंने मिजोरम में 48 रेलवे सुरंग और अनेक रेलवे पुल बनाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ''यह जादूगर का काम है। अश्विनी वैष्णव एक जादूगर हैं।''

पूर्वोत्तर की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वैष्णव को धन्यवाद देते हुए तापिर गाव ने कहा, ''अरुणाचल प्रदेश में तो मेरे गृह नगर में, मेरे खेत में ही स्टेशन बना दिया। वर्ष के अंत में वह उदघाटन करने जाएंगे।''

भाजपा सांसद ने कहा, ''सही मायने में 'अष्टलक्ष्मी' बना रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव ही बना रहे हैं। मोदी जी राम हैं तो ये (अश्विनी) हनुमान हैं। जहां इशारा किया उस जगह को रेलवे से जोड़ रहे हैं।''

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ प्रदेशों को 'अष्टलक्ष्मी' नाम दिया है।

तापिर गाव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आने वाले समय में दूसरे देशों के रेल मंत्रालय वैष्णव से पूछेंगे कि रेल सुरंग कैसे बनाई जाती हैं, मिजोरम में कुतुब मीनार से ऊंचा पुल बनाकर वहां रेल मार्ग उन्होंने कैसे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, ''यह रेल मंत्री की रचनात्मकता है कि हर रेलवे स्टेशन को शॉपिंग मॉल जैसा बना दिया।''

शिव भक्ति में डूबे कैलाश खेर, बाबा कालभैरव मंदिर में गाया 'बम बम लहरी' भजन

वाराणसी/एजेन्सी

देश के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक, संगीतकार और शिव भक्त कैलाश खेर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बाबा कालभैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। पार्श्व गायक ने मंदिर में पूजा के समय अपना प्रसिद्ध शिव भजन 'बम बम लहरी' गाकर बाबा को समर्पित किया। इस दौरान वह माथे पर चंदन, गले में फूल और रुद्राक्ष की माला और हाथ में फूलों की टोकरी लेकर खड़े दिख रहे हैं।

मंदिर प्रांगण में कैलाश खेर के साथ भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला, सभी बाबा की भक्ति में मगन दिखे। वाराणसी स्थित बाबा कालभैरव मंदिर, भगवान शिव के उग्र रूप 'कालभैरव' को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिन्हें 'काशी का कोतवाल' माना जाता है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले भक्तों को कालभैरव की आज्ञा लेनी होती है, वरना उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है।

बाबा कालभैरव मंदिर की खासियत है कि यहां शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है और यह मंदिर 17वीं सदी का माना जाता है, जो कि देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहां आते हैं।

वहीं, कैलाश खेर देश के एक प्रमुख और लोकप्रिय गायकों में से एक हैं, जो अपनी अनूठी और

दमदार आवाज के साथ सूफी-लोक संगीत शैली के लिए जाने जाते हैं। गायक ने बॉलीवुड में 300 से अधिक गीतों में अपनी बेमिसाल आवाज दी है। कैलाश खेर के कुछ प्रमुख हिंदी गानों में 'अल्लाह के बंदे', 'संइया', 'तेरी दीवानी', 'या रब्बा', 'पिया घर आवेंगे', 'चांद सिफारिश', 'यूं ही चला चल', 'तौबा तौबा' आदि गाने शामिल हैं। अपनी उत्कृष्ट गायकी के लिए उन्हें 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। शिव भक्त कैलाश खेर हिंदी फिल्मों के गानों के साथ-साथ कई शिव भजन और स्तुति के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं। उनमें से कुछ प्रमुख 'शिव शंभो', 'बम बम लहरी', 'आदियोगी', 'शिवोहम', 'अनादि अनंता', 'जय जय केदारा', 'कर्पूर गौरम', 'महामृत्युंजय मंत्र' और 'कौन है वो कहां से आया' आदि भजन शामिल हैं।

परेड

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के एसटीसी तलवारा में आयोजित पुलिस कांस्टेबलों की 'पासिंग आउट परेड' में हिस्सा लिया। उन्होंने नए कैडेटों को सम्मानित किया और उन्हें निष्ठापूर्वक सेवा करने की शपथ दिलाई।

ईरान, लेबनान और अन्य पश्चिम एशियाई देशों को मानवीय सहायता प्रदान करेगा चीन

बीजिंग/भाषा। चीन ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान, लेबनान और क्षेत्र में जारी संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित दो अन्य पश्चिम एशियाई देशों को आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करेगा।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेसवार्ता में बताया कि बीजिंग ने स्थानीय लोगों द्वारा सामना की जा रही दिक्कतों को कम करने की उम्मीद में ईरान, जॉर्डन, लेबनान और इराक को आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

लिन ने कहा, ''मौजूदा समय में जारी पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। चीन संबंधित देशों के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है।'' वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या चीन संबंधित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि पश्चिम एशिया में संकट एक बड़ा मानवीय आपातकाल बन गया है, और इन क्षेत्रों में पहले से ही लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं।

लिन ने कहा कि ईरान में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई है, जबकि लेबनान में लगभग 8,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं तथा जॉर्डन, इराक और अन्य देश भी प्रभावित हुए हैं।

पिछले सप्ताह, चीन ने अमेरिका-इजराइल और ईरान संघर्ष के दौरान ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हालिया बम हमले में मारे गए पीड़ितों के परिजनों के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता के रूप में 2,00,000 अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी।

अब 'क्लीन मुंबई' के लिए भिड़ेंगे मुंबईकर, अक्षय कुमार लेकर आए अनोखा कॉम्पिटिशन

मुंबई/एजेन्सी

मायानगरी मुंबई में हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए आता है , लेकिन बढ़ती गंदगी और जहरीली हवा ने इस शहर की चमक को अब फीका सा कर दिया है। इसी समस्या को देखते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने 'मुंबई क्लीन लीग' की शुरुआत कर दी है। हाल ही में उन्होंने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में इसके पीछे का मुख्य कारण बताया। एक्टर ने बताया कि इस लीग का मुख्य आइडिया इंडियन प्रीमियर लीग से लिया गया है। इसमें एक बहुत ही कमर्शियल स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट लीग के तत्वों को नागरिक जिम्मेदारियों के साथ मिलाया गया है। अक्षय कुमार ने कहा, आईपीएल (इंडियन प्रीमियम लीग) देखकर मेरे मन में इसका विचार आया। इसके बाद मैंने अमित साटम जी से कहा कि क्यों न हम एक 'मुंबई क्लीन लीग' बनाएं? मुंबई में कई तरह के लोग रहते हैं और हर कोई एक अच्छी जिंदगी चाहता है, हालांकि मुंबई में जगह कम है, लेकिन यहां के लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। यह देश का आर्थिक केंद्र है। हर कोई यहां साफ और प्रदूषण-मुक्त माहौल में खुशी से रहना चाहता है।

अक्षय कुमार ने आगे स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा, स्कूल में स्पोर्ट्स डे, एलोकेशन डे और मॉनिटर सिस्टम होता था और हर किसी में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आने की होड़ लगती थी। उसी तरह यह लीग होगी, जहां पूरा मुंबई हिस्सा लेगा और कॉम्पिटिशन में उतरेगा। अभिनेता ने अपनी बातों से समझाया कि इस लीग से उनका मकसद मुंबई जैसे शहर को साफ और स्वच्छ बनाना है, हालांकि लीग की शुरुआत की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

समारोह

थाईलैंड द्वारा आयोजित दूसरा अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह मंगलवार को महाबोधि मंदिर में शुरू हुआ। इसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं और दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और शांति का संदेश दिया।

वामिका गब्बी से अक्षय कुमार भी मान गए हार

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता अक्षय कुमार अपनी जबरदस्त एक्टिंग और फिटनेस के लिए चर्चा में रहते हैं। लेकिन, इस बार उन्हें अभिनेत्री वामिका गब्बी ने मजेदार तरीके से मात दी है। वामिका ने इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार के साथ एक फनी वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में अक्षय कुमार और वामिका प्लेन पर बैठकर पंजा लड़ा रहे हैं।

दोनों जोर-शोर से एक-दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि तभी वीडियो में ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल, मुकाबले के बीच अचानक से किसी ने उसी टेबल पर वामिका की लिपस्टिक रख दी थी, जिसे देखते ही अभिनेत्री जोर से चिल्लाती हैं, अरे मेरी लिपस्टिक।ये आवाज सुनते ही अक्षय इतने चौंक जाते हैं कि उनका ध्यान भटक जाता है, जिससे वे मुकाबला हार जाते हैं। वीडियो को दोनों स्टार्स ने हास्य अंदाज में पेश किया।वहीं, वीडियो के जरिए वामिका ने दिखाया कि लड़कियां अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर कितनी सजग रहती हैं। छोटी-सी चीज भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

वीडियो पोस्ट करते हुए वामिका ने लिखा, 10 अप्रैल को 'भूत बंगला' में जाने से पहले थोड़ी सी 'खिलाड़ी' वाली एनर्जी। वैसे, मेरे पास वही एक लिपस्टिक थी, इसलिए वह मेरे लिए काफी जरूरी थी।वामिका के इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स पसंद कर रहे हैं। वहीं, अक्षय कुमार ने कमेंट करते हुए लिखा, एक बात समझ में आ गई। कभी भी किसी लड़की और उसकी लिपस्टिक के बीच में मत आओ। उस लड़ाई में 'खिलाड़ी' भी हार जाएगा।प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका और परेश रावल के अलावा, तब्बू, राजपाल यादव और मिथिला पालकर भी अहम रोल में नजर आएंगी। कॉमेडी-हॉरर फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है। यह प्रियदर्शन की दूसरी हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 'भूलभुलैया' बनाई थी।

मृणाल ठाकुर ने किए श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दर्शन

मुंबई/एजेन्सी

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने हिंदी, मराठी और तेलुगु सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग के बलबूते इंडस्ट्री के साथ लोगों के दिलों में एक खास पहचान बनाई है। मंगलवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे देश के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिरों में से एक श्रीमंत दगड़शेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा का दर्शन करते नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने बप्पा के साथ कुछ बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों को फैंस के साथ शेयर किया है, इसी के साथ वो पोस्ट कैप्शन में लिखती हैं, पुण्यात आलो आणि बाप्पाचं दर्शन घेतलं नाही तर काय केलं? यानी अगर पुणे आए और बप्पा (भगवान गणेश) के दर्शन नहीं किए, तो फिर क्या किया? मृणाल ठाकुर के इस पोस्ट को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। क्या आपको देश के इस

प्रसिद्ध और प्राचीन श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के बारे में जानकारी है? अगर नहीं, तो आइए हम आपको बताते हैं, श्रीमंत दगड़शेठ हलवाई मंदिर देश के सबसे धनी, प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है।

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर महाराष्ट्र के पुणे के बुधवार पेठ क्षेत्र में शनिवार वाडा के पास स्थित है। सोना और चांदी से सजे इस मंदिर की विरासत 125 साल से अधिक पुरानी है। मंदिर की स्थापना पुणे के एक प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता, दगडूशेठ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने 1893 में की थी।

दगडूशेठ हलवाई ने अपने बेटे की प्लेग महामारी में मृत्यु हो जाने के बाद गुरु माधवनाथ महाराज के कहने पर शहर के बीचोंबीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया। आराध्य गणेश जी को समर्पित इस मंदिर की भव्यता और प्रभु के प्रतिमा का सौंदर्य अद्भुत है। मंदिर में गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जो कि विश्वभर में प्रसिद्ध है। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर-दराज से प्रयर्टक और श्रद्धालु आते हैं।

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का बदला नाम, अब 'मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस' के नाम से होगी रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पिछले कुछ समय से अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी के घटनाक्रम से प्रेरित बताई जा रही है। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है।

दरअसल, फिल्म के मेकर्स ने रिलीज से पहले इसका नाम बदल दिया है, जिससे फैंस के बीच फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, सोमवार को सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म के नए नाम की घोषणा की। अब यह फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के नाम से रिलीज होगी। पहले इस प्रोजेक्ट को 'बैटल ऑफ गलवां' के नाम से जाना जा रहा था।

नाम बदलने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर भी जारी किया, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। इस पोस्टर में सलमान खान बेहद अलग और गंभीर नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खून और जख्म साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके माथे पर गहरी चोट है और चेहरा धूल-मिट्टी से भरा हुआ है। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिला-जुला भाव है।

पोस्टर में सबसे ध्यान खींचने वाला हिस्सा एक ऐसा हथियार है जिसे वह अपने हाथ से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हथियार के ऊपर कांटेदार तार लिपटा हुआ है और उस पर खून के निशान भी दिखाई देते हैं। वहीं, बैकग्राउंड को धुएं और धूल से भरा हुआ दिखाया गया है; इसमें कुछ सैनिक हथियार के साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर का माहौल युद्ध जैसा महसूस होता है।

सलमान खान ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस', यानी युद्ध का अंत हो और शांति कायम रहे। फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति संभालते हैं। वहीं उनके साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा, अभिनेता अभिलाष चौधरी और अंकुर भाटिया भी फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे।

शुरुआत में दिन-रात करता था लगातार काम, अब समझ आई जिंदगी में संतुलन की अहमियत : हितेन तेजवानी

नई दिल्ली/एजेन्सी

टीवी इंडस्ट्री की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। कलाकारों को लगातार शूटिंग करनी पड़ती है और कई बार दिन-रात काम करना पड़ता है। इस कड़ी में टीवी अभिनेता हितेन तेजवानी ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती सालों की मेहनत और आज के बदले हुए नजरिए के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था, जब वह 24 घंटे में करीब 18 से 19 घंटे तक काम किया करते थे। हितेन तेजवानी ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा, ''टीवी इंडस्ट्री में शुरुआत के समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ काम पर ही रहता था। उस समय मैं लगातार शूटिंग में बिजी रहता था, नींद के लिए बहुत कम समय मिल पाता था और बाकी किसी चीज के बारे में सोचने का समय भी नहीं होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं 24 घंटे में 18 से 19 घंटे तक लगातार काम करता रहता था और मुश्किल से कुछ घंटे ही सो पाता था।''

हितेन ने कहा, ''उस समय मेरे अंदर काम को लेकर जबरदस्त जुनून था। मैं सिर्फ यही सोचता था कि मैं अपने काम को और बेहतर कैसे करूं। वही मेहनत और लगातार काम करने का जज्बा मुझे

आज इस मुकाम तक लेकर आया है। अगर मैंने उस समय इतनी मेहनत न की होती, तो शायद आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता और इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक भी नहीं पाता।''अभिनेता ने कहा, ''समय के साथ इंसान का नजरिया बदलता है। दो दशक से ज्यादा समय तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद अब मुझे यह महसूस होता है कि जिंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता। लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद एक ऐसा दौर आता है, जब इंसान को संतुलन की अहमियत समझ आने लगती है। अब मैं कोशिश करता हूं कि काम के घंटे सीमित हों, ताकि मुझे आराम और परिवार के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके।''

हितेन ने कहा, ''आज मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखता हूं कि जीवन के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज न करूं। परिवार के साथ समय बिताऊं, आराम करूं और मानसिक शांति बनाए रखूं, क्योंकि यह उतना ही जरूरी है, जितना कि पेशेवर सफलता हासिल करना।'' बातचीत के दौरान उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले नए कलाकारों को भी सलाह दी। हितेन ने कहा, ''जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए। उन्हें यह जानना चाहिए कि उनकी ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं। जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, तभी वह उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है।

स्पीड पोस्ट

बेंगलूरु के जनरल पोस्ट ऑफिस में चीफ पोस्टमास्टर जनरल के. प्रकाश ने 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट प्रीमियम सेवाओं का शुभारंभ किया।

रायचूर जिले में नई केएसआरपी फोर्स की स्थापना की समीक्षा : परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। रायचूर जिले में नई केएसआरपी फोर्स स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि आवश्यकता के आधार पर रायचूर जिले में केएसआरपी फोर्स की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, मस्की निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बसनागौड़ा तुरुविहाल ने कहा कि कल्याणा, कर्नाटक में केएसआरपी बल की आवश्यकता है और इसके लिए 175 एकड़ भूमि और केकेआरडीबी अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। कल्याणा कर्नाटक के सभी विधायकों ने गृह मंत्री को पहले ही अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने सदन से इस संबंध में केएसआरपी बल के गठन के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस समय जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि रायचूर क्षेत्र के 30 विधायकों ने रायचूर क्षेत्र में केएसपी बल स्थापित करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु सहित राज्य में पहले से ही 12 केएसपी बल कार्यरत हैं। रायचूर में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, बांध और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण विधायकों के अनुरोध पर वित्त विभाग को प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। गृह मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद आवश्यकतानुसार केएसपी बल की स्थापना के लिए कार्रवाई की जाएगी।

पीन्या कराबीनि अस्पताल में एक दिवसीय पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला संपन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कराबीनि) अस्पताल, पीन्या में एक दिवसीय पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंगलवार को डॉ. मृदुला एएम ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपनिदेशक सुभाषचंद्र लाल व प्रियरंजन आदि उपस्थित थे।

निगम का प्रतीक चिह्न 'पंचदीप' का प्रज्वलन कर कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटित करते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम सभी हिंदी जानते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में दसवीं कक्षा में पढ़ा है, लेकिन कार्यालय में हिंदी में कार्य करने में हमें अभ्यास नहीं हो पाता है। इसके लिए ही हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। राजभाषा का प्रयोग हम सबका संवैधानिक दायित्व है, उन्होंने यह भी कहा कि हमें सरकार द्वारा जारी विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कार्यशाला में राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के बहुत सारे विकल्प, राजभाषा की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं एवं प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्थाओं के साथ-साथ, नेमी टिप्पणियों तथा प्रशासनिक शब्दावली का अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों को हिंदी में टंकण करने तथा टंकण में गति बढ़ाने के गुर भी सिखाए गए। समापन समारोह में चिकित्सा अधीक्षक ने विजेताओं को राजभाषा हिंदी से संबंधी एक पुस्तक एवं प्रमाण पत्र वितरित की।कार्यक्रम का संचालन व आभार व्यक्त कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी कैलाशचंद शर्मा ने किया।

निष्ठा और समर्पण से ही मिलती है कार्य में सफलता : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

धारवाड़। उत्तर कर्नाटक की यात्रा के दौरान चार दिन के प्रवास पर धारवाड़ पहुंचे आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने मंगलवार को धारवाड़ के शीतलनाथ जैन संघ में आचार्यश्री ने कहा कि चाहे धर्म का क्षेत्र हो या व्यवहार का, किसी भी कार्य के लिए मनुष्य का समर्पण भाव ही उसकी सफलता की कुंजी है। बिना समर्पण के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता।

आराध्य की उपासना हो या धनोपार्जन अथवा विद्या-अध्ययन, हर कार्य में गंभीरता, निष्ठाभावना और मन की तल्लीनता जरूरी होती है। जहां मनुष्य का मन लगता है, वहां शक्तियों का सृजन होता है। फिर कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। आज सबसे बड़ी समस्या समर्पण भाव के अभाव की है। जैनाचार्य ने कहा कि लोग बिना मन के कई काम करते रहते हैं। फिर जब कार्यसिद्धि नहीं होती तो थक जाते हैं अथवा हार कर उस कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। विशेषकर विद्यार्थियों, नए व्यापारियों तथा नए साधकों के साथ ऐसा अकसर होता है। कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, अनेक लोग बार-बार नौकरी या व्यवसाय बदलते हैं तो अनेक साधक साधना अधूरी ही छोड़ देते हैं। यह सब मनुष्य के मन की कमजोरी है।

जहां ध्येय के प्रति समर्पण नहीं होता, वहां सिद्धि असंभव है। जहां कार्य के प्रति निष्ठाभावना और गहरी लगन है, वहां मुश्किलें भी सफलता की राह बन जाती हैं। इस दुनिया में जो भी मूल्यवान वस्तु है, वह कभी सरलता से नहीं मिलती और समर्पित होकर की गई मेहनत कभी निष्फल भी नहीं जाती।ङ्कङ्कसंघ में आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने संघीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया और समाज को आवश्यक हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि धर्म और समाज के कार्यों के प्रति उदासीन रवैया ही हमारी अवनति एवं समस्याओं का मूल कारण है। संघीय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और उसमें हर सदस्य की भूमिका तथा जिम्मेदारी होनी चाहिए।

जवाबदेही तय करके ही हम धर्मसंघ को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। जैनाचार्य ने यहां शीतलनाथ जैन मंदिर में दो महीने में दो बार हुई चोरी की वारदातों के लिए दुःख व्यक्त किया और पुलिस प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही कर चोरों को पकड़ने का आग्रह किया। गणि पद्मविमलसागरजी ने कहा कि देव, गुरु और धर्म अपने घर-परिवार की तरह लगने चाहिए, जब ऐसा होगा तभी भक्ति सार्थक होगी।

पर्यावरण संरक्षण पहल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के जेसीआई कॉस्मो के सदस्यों ने 'स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीसिप-सस्टेनेबल सिपिंग पहल के तहत ऑटो ड्राइवर, बीबीएमपी कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर और सब्जी विक्रेताओं को पानी पीने के लिए प्लास्टिक बोतल के जगह स्टील की बोतलें वितरित की गईं। अध्यक्ष ललिता, उपाध्यक्ष(कम्युनिटी डेवलपमेंट) ममता मेहता, संयोजक मनीष मेहता, कोषाध्यक्ष दीपिका जैन, मोनिश मुथा, श्वेता राखेचा और तरुण भंसाली ने रूपचंद समकित कुमट और सचिता जैन द्वारा प्रायोजित स्टील बोतलें लोगों को वितरित की।

बेंगलूरु में बदला मौसम का मिजाज, बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत

ओले गिरने से लोगों को असुविधा भी हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु में मंगलवार शाम को मौसम का मिजाज बदल गया और झूमकर बादल बरसे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं, ओले भी गिरे, जिससे लोगों, खासकर दुपहिया वाहन चालकों को असुविधा हुई। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। इससे कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई और शहरवासियों ने राहत महसूस की। अचानक बेंगलूरु उत्तर में ओले गिरने से राहगीर और बाइक सवार सुरक्षित जगह ढूंढ़ने लगे।

ओलों की चपेट में आने से कुछ गाड़ियों के शीशे प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। उनमें ओले गिरने की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही है। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बेंगलूरु में बारिश के साथ ओलों की बौछार ... इनकी आवाज सुनकर लगा कोई मशीन चल रही है।' कई जगह लोग ओलों को हाथों में उठाते और उनके ढेर लगाते नजर आए। बता दें कि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। अगले तीन दिनों में और बारिश होने का अनुमान है। सोमवार को उत्तर कर्नाटक में बारिश हुई, जहां ओले भी गिरे थे। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 मार्च तक कर्नाटक के उत्तरी और तटीय हिस्सों, जिनमें मलनाड, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कासरगोड, धारवाड़ और बेलगावी जिले शामिल हैं, में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हासन, चिक्कमगलूरु और शिवमोग्गा जिलों के कुछ हिस्सों में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

सोमवार को धारवाड़, बेलगावी, हावेरी, बागलकोट, विजयनगर, कोप्पल और रायचूर के कई इलाकों में बारिश हुई थी। वहीं, बेंगलूरु में लगभग दो हफ्तों की तेज गर्मी के बाद मौसम सुहावना हो गया है।

जीतो द्वारा नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप 9 अप्रैल को, तैयारियां शुरू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन(जीतो) नॉर्थ एवं साउथ चैप्टर द्वारा टाउनहॉल में आगामी 9 अप्रैल आयोजित होने वाले नवकार दिवस की औपचारिक घोषणा की गई। समाज को एक सूत्र में जोड़ने व नवकार महामंत्र की महिमा को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह आयोजन फ्रीडम पार्क में होगा। आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष एक लाख से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस घोषणा के मौके पर साउथ के चेयरमैन रणजीत सोलंकी, महामंत्री नितिन लुनिया, नॉर्थ के चेयरमैन विमल कटारिया, महामंत्री विजय सिंघवी, नार्थ के संयोजक प्रवीण चौहान, सहसंयोजक सुनील लोढ़ा, साउथ के संयोजक महेंद्र रांका, सहसंयोजक महावीर दांतेवाड़िया सहित श्रीपाल बच्छावत, महेंद्र जियानी, राजकुमार कोठारी, राजेंद्र दांतेवाड़िया, कमल पुनमिया, दिनेश बाफना, बबीता रायसोनी, लक्ष्मी बाफना, मेहुल श्रीश्रीमाल एवं अनीश भोजानी आदि उपस्थित थे।

निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 63 लोगों ने करवाई शल्य चिकित्सा

मैसूरु/दक्षिण भारत। जिले के बन्नूर कस्बा स्थित रोटरी स्कूल में कोयम्बटूर के अरविंद नेत्र चिकित्सालय के डॉ. विकास कुमार, डॉ. धर्मेंद्र कुमार तथा शिविर संयोजक विजयगंथ बीके की देखरेख में गवरीदेवी-कानसिंह राजपुरोहित की ओर से शनिवार को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर रखा गया था, शिविर में चिकित्सकीय परामर्श के बाद 63 लोगों को चिन्हित कर आंखों के ऑपरेशन हेतु अरविंद नेत्र चिकित्सालय ले जाया गया। मंगलवार को सभी मरीज आंखों का ऑपरेशन करवा कर पुनः बन्नूर लौटे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अणुव्रत डायरी वितरण

अणुविभा के 'अणुव्रत' प्रकल्प के प्रचार-प्रसार के लिए देशभर में 'अणुव्रत डायरी' का व्यापक स्तर पर वितरण किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में संगठन मंत्री राजेश चावत ने बेंगलूरु के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों से विशेष मुलाकात कर उन्हें अणुव्रत डायरी भेंट की। इस महत्वपूर्ण अभियान का मुख्य उद्देश्य डायरी में समाहित अणुव्रत के नियमों और विषयों की विस्तृत जानकारी को बुद्धिजीवियों सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है।

गौसेवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के मारुति मेडिकल्स के मालिक व जाने माने गौसेवक महेन्द्र मुणोत ने उत्तराहल्ली स्थित ओंकार हिल्स पर बने ओंकार आश्रम में संचालित ओंकारेश्वर गो सेवा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि बजरंगलाल चौधरी और दिनेश राजपुरोहित को गायों की सेवा के लिए दो लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस मौके पर आनंद मुणोत भी उपस्थित थे। मुणोत ने कहा कि गायों की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

प्रदर्शन

बेंगलूरु के मैजेस्टिक स्थित डीआरएम कार्यालय पर कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने रेलवे विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रेलवे परीक्षाओं में कन्नड़ भाषा की अनदेखी की जा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

राजग ने केरल में ईसाई बहुल दो निर्वाचन क्षेत्रों में पिता-पुत्र को मैदान में उतारा

कोट्टायम/भाषा

केरल में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दक्षिणी कोट्टायम जिले में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पिता और पुत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार के रूप में दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों सीटों पर ईसाई मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। ये और कोई नहीं, बल्कि वरिष्ठ नेता पी.सी. जॉर्ज और उनके बेटे शोन जॉर्ज हैं। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के साथ ही पिता-पुत्र को क्रमशः पूंजार और पाला सीटों से मैदान में उतारा गया है। ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र केरल के मध्य हिस्से में स्थित हैं और यहां ईसाई मतदाताओं का प्रभाव अधिक है।

सात बार विधायक रहे पी सी जॉर्ज अपने गृह क्षेत्र पूंजार में जाना-माना नाम हैं। वह तीन दशकों से अधिक समय तक राज्य विधानसभा के सदस्य रहे और केरल कांग्रेस के विभिन्न गुटों में रहने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी केरल जनपक्षम (धर्मनिरपेक्ष) का गठन किया था। उन्होंने 1981, 82, 1996, 2001 और 2006 में विधानसभा में पूंजार का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनावों में अपने गृह क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और तीन प्रमुख मोर्चों को हराकर जीत हासिल की।

उनकी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा-राजग गठबंधन में विलय हो गया था। इसी बीच, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शोन जॉर्ज ने कहा कि उनके पिता और वह दोनों एक ही चुनाव में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने जोर दिया कि वे पूंजार और पास के पाला निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ें।

उन्होंने मंगलवार को यहां कहा, एक ही परिवार से दो व्यक्तियों का चुनाव लड़ना कई मुश्किलें खड़ी करता है। लेकिन नेतृत्व ने हमें बताया कि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी लड़ रही है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पाला निर्वाचन क्षेत्र में, शोन जॉर्ज का मुकाबला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) नेता और केरल कांग्रेस (मणि) के प्रमुख जोस के मणि और मौजूदा एकीकृत लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) विधायक मणि सी कप्पन से है।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**